● वर्ष-4
● अंक-146
रायपुर, बुधवार
29 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» परिस्थितियों का करें पूरी...

दिल्ली फतह: भाजपा ने की तगड़ी तैयारी

27 दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा

नईदिल्ली। आगामी दिल्ली विधान सभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत लगा रही है। दिल्ली फतह को लेकर भाजपा ने तगड़ा प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 27 प्रमुख नेताओं की एक टीम बनाई है जिसमें केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री और व्यापक संगठनात्मक अनुभव वाले वरिष्ठ पार्टी नेता शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेन्द्र यादव, गजेंद्र शेखावत, मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर, विनोद तावड़े, ब्रजेश पाठक, नरोत्तम मिश्रा और अन्य प्रमुख नेता इस टीम का हिस्सा हैं।

ये नेता भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के साथ, निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक प्रबंधन की देखरेख करेंगे। प्रत्येक नेता को दो निर्वाचन क्षेत्रों में जीत सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। कुल मिलाकर, टीम दिल्ली भर में 54 निर्वाचन क्षेत्रों को जीतने पर ध्यान केंद्रित करेगी। पीयूष गोयल को दिल्ली कैंट और वज़ीरपुर निर्वाचन क्षेत्रों का राजनीतिक प्रबंधन

सौंपा गया है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश निर्वाचन क्षेत्रों का प्रबंधन करेंगे।

भूपेन्द्र यादव महरौली और बिजवासन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार हैं जबकि मनसुख मंडाविया शकूर बस्ती और मादीपुर निर्वाचन क्षेत्रों की देखरेख करेंगे। गजेंद्र शेखावत नरेला और बवाना विधानसभा क्षेत्र संभालेंगे। इसके अतिरिक्त, देश भर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं को अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आदर्श नगर और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र संभालेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल शालीमार बाग और त्रिनगर निर्वाचन क्षेत्रों की देखभाल करेंगे, जबकि एक अन्य राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जनकपुरी और उत्तम नगर निर्वाचन क्षेत्रों की देखरेख करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव, तरुण चुघ, लक्ष्मी नगर और कृष्णा नगर के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि एक अन्य राष्ट्रीय महासचिव, अरुण सिंह, मॉडल टाउन और मोती नगर निर्वाचन क्षेत्रों का प्रबंधन करेंगे। अन्य राज्यों के प्रमुख भाजपा नेता, जैसे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब, बिहार से विवेक ठाकुर, उत्तर प्रदेश से अनिल जैन, झारखंड से निशिकांत दुबे, राजस्थान से सुरेंद्र नागर और तेलंगाना से अरविंद धर्मपुरी भी दिल्ली के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के लिए राजनीतिक रणनीतियों का प्रबंधन में शामिल हैं। ये नेता स्थानीय उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिन-प्रतिदिन की अभियान गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं।

दिल्ली के रण में उतरे राहुल गांधी

कांग्रेस दिल्ली चुनाव में अपनी ताकत लगा रही है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पार्टी के लिए प्रचार किया। वेस्ट विनोद नगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल के मन में जो आए वो बोल देते हैं, जब वो आए थे तो उनके पास एक छोटी सी कार थी और उन्होंने कहा था कि वो नई तरह की राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली को बदल देंगे लेकिन जब गरीबों को जरूरत थी तो वो वहां नहीं थे, जब दंगे हुए तो वो वहां नहीं थे।

राहुल ने दावा किया कि केजरीवाल ने कहा था कि वो साफ-सुथरी राजनीति करेंगे, लेकिन दिल्ली में शराब का सबसे बड़ा घोटाला हुआ और आपने उनके घर की फोटो देखी होगी। केजरीवाल एक महल शीश महल में रहते हैं। तो ये है सचाई। भाजपा पर वार करते हुए राहुल ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा-आरएसएस के लोग हैं, जो देश में नफरत और हिंसा फैलाते है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारी विचारधारा है। हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हमें नफरत, डर और हिंसा वाला हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए।राहुल ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि वे महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण, टूटी सड़कों के बारे में नहीं दिखाते। वे नरेंद्र मोदी का चेहरा और अंबानी जी की शादी दिखाते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार संदीप दीक्षित के समर्थन में मंगलवार को प्रचार किया और कई स्थानीय मतदाताओं से संवाद किया।

मौनी अमावस्या पर बड़ा अमृत स्नान आज

महाकुंभनगर। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में कल यानि बुधवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान होना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी यहां के इंतजाम पर नजर रख रहा है। महाकुंभ क्षेत्र और उससे पहले के बड़े हिस्से को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। अमावस्या को आठ से दस करोड़ तक लोगों के आने की संभावना है। इसलिए मेला क्षेत्र में चल रहे सेंट्रल हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। अभी तक ओपीडी सेवाएं 12 घंटे ही दी जा रही थीं। परेड मैदान पर बनाए गए 100 बेड के सेंट्रल अस्पताल के अलावा 20 अन्य स्थानों पर बने छोटे अस्पतालों में भी 24 घंटे ओपीडी 30 तारीख तक चलेगीं।

महाकुंभ मेला 2025 में अब तक 18 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई हैं। मौनी अमावस्या से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या से दो दिन पहले ही लाखों आस्थावान संगम में डुबकी लगाने को उमड़ पड़े। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले दो दिनों में यानी रविवार और सोमवार को तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम और उससे सटे गंगा के घाटों पर स्नान कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया।

मौनी अमावस्या पर आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी और डीआरएम हिमांशु बडोनी ने प्रयागराज जंक्शन और खुसरोबाग में बने यात्री आश्रय का निरीक्षण किया। डीआरएम ने बताया कि जंक्शन में श्रद्धालुओं को यात्री आश्रय शेड के माध्यम से ही प्रवेश दिया जाएगा। यात्री आश्रय शेड में स्थान न होने की स्थिति में खुसरोबाग का प्रयोग यात्री आश्रय के रूप में किया जाएगा। पांच अलग-अलग रंगों से आश्रय के गेटों को रंगा गया। इससे दिशावार जाने वाले यात्रियों को जंक्शन पर प्रवेश मिलेगा।मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए कुंभ पुलिस ने 5 फरवरी तक मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण ने कहा कि 5 फरवरी को सुबह 8 बजे या भीड़ समाप्ति तक महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रशासनिक और मेडिकल वाहनों के अलावा सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

रायपुर। राजनांदगांव में महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव ने नामांकन भरा जिसमें रमन सिंह शामिल हुए। रमन सिंह ने कहा ,आज राजनांदगांव नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव के नामांकन के लिए कलेक्टर परिसर पहुंचकर शामिल हुआ।

खड़गे के बयान पर अमित शाह का पलटवार, केजरीवाल पर भी जमकर साधा निशाना

आपने गरीबों का क्या भला किया...

नईदिल्ली। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि दिल्ली को आप-दा के कुशासन व भ्रष्टाचार के अंधकार से निकालने का एकमात्र विकल्प 'भाजपा' है। कालकाजी विधानसभा में भाजपा ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। शाह ने कहा कि 5 तारीख को दिल्लीवालों के लिए केजरीवाल की आप-दा से मुक्त होने का बहुत बड़ा मौका है। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाइए और केजरीवाल की आप-दा से हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। केजरीवाल की सरकार झूठ, फरेब, वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार की सरकार है।

अमित शाह ने कहा कि कल केजरीवाल ने जलबोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देकर एक बयान दिया कि दिल्ली में जो यमुना का पानी आता है, उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। जबकि जलबोर्ड वालों ने कहा कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी, आपके पास जलबोर्ड की जो रिपोर्ट है, उसे कल सार्वजनिक ?कीजिए, हम जिम्मेदारी लेंगे। शाह ने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान इन्होंने (केजरीवाल) कहा था कि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन इन्होंने पार्टी बनाई। इन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, कांग्रेस का समर्थन लिया। इन्होंने कहा था कि हम सिक्योरिटी, गाड़ी और बंगला नहीं लेंगे, इन्होंने सिक्योरिटी ली, गाड़ी ली और करोड़ों का शीश महल बनवाया।उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, इन्होंने हजारों करोड़ रुपये का शराब घोटाला किया। मंदिर, गुरुद्वारा, स्कूल... सबके सामने शराब की दुकानें खोलीं, जेल गए।जलबोर्ड घोटाला, राशन घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, क्लासरूम घोटाला किया और खुद के लिए करोड़ों का शीश महल बनवाया। शाह ने खड़गे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जारी रखते हुए कहा कि अभी कल मैंने महाकुंभ में गंगा की डुबकी लगाई, लेकिन डुबकी मैंने लगाई और ठंड खड़गे जी को लग गई। वो कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाई, लेकिन आपने गरीबों का क्या भला किया।

अमित शाह ने कहा कि भाजपा पार्टी इस देश की परंपरा और आस्था में विश्वास करती है, इसलिए भव्य करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनता है और महाकुंभ का मेला भी लगता है।

प्रमुख समाचार

वक्फ विधेयक का मुस्लिम मंच ने स्वागत किया

नईदिल्ली। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) के संयोजक शाहिद सईद ने मंगलवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी मिलने का स्वागत किया और इसे वंचित समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वंचितों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाते हुए बुनियादी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में काम करेगा। शाहिद सईद ने बताया कि यह कामयाबी मंच की मेहनत, संघर्ष और जागरूकता अभियानों का परिणाम है, जिसमें देशभर में 1000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित कर जनता को विधेयक की प्रासंगिकता समझाई गई। इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभिन्न संगठनों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने जेपीसी के समक्ष पेश हो कर अपनी दलीलों को प्राथमिकता से रखा। साथ ही मंच के देश भर में फैले कार्यकर्ताओं ने लाखों की तादाद में जेपीसी को पत्र और मेल के द्वारा समर्थन और सुझाव रखे। इन सभी को जेपीसी ने पूरी गंभीरता के साथ लिया। इस दौरान जेपीसी में विपक्षी नेताओं की तीव्र आलोचना भी मंच के सदस्यों को सुननी पड़ी लेकिन मंच के नुमाइंदों ने सहजता, सरलता, साक्ष्यों, तर्क और पूरी शिद्दत के साथ अपने सुझाव रखे।

जब तक मांगें मानी नहीं जातीं अनशन जारी रहेगा: डल्लेवाल

चंडीगढ़ । पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती तब तक वह अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। डल्लेवाल ने

खनौरी धरना स्थल पर मीडिया से कहा कि पूरे देश को एमएसपी की जरूरत है। उन्होंने विस्तार से बताए बिना कहा, ''पंजाब को भी अपने भूमिगत जल स्तर को बचाने के लिए एमएसपी की जरूरत है।'' केंद्र सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 18 जनवरी को आंदोलनकारी किसानों को उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ में 14 फरवरी को बैठक के लिए आमंत्रित किया था जिसके बाद से डल्लेवाल ने चिकित्सकीय सहायता लेनी शुरू कर दी लेकिन उन्होंने अपना अनशन समाप्त नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक डल्लेवाल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले साल 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं।

सीपीएम कार्यकर्ताओं ने प्रियंका को दिखाए काले झंडे

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को केरल में उनके निर्वाचन क्षेत्र वायनाड के दौरे के दौरान सीपीएम कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे मानव-पशु संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए, एक घातक बाघ के हमले पर देरी से प्रतिक्रिया देने के लिए उनकी आलोचना की।

स्थानीय लोग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को केरल के वायनाड का दौरा किया और राधा के परिवार से मुलाकात की, जो हाल ही में कनियारम, मननथावाडी में बाघ के हमले में मारी गई थी। गांधी की यात्रा क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष पर बढ़ती चिंताओं के बीच हो रही है, जिसमें हाथियों के हमले के तीन पीड़ितों सहित चार लोगों की जान चली गई है। यहाँ मानव-पशु का यह मुद्दा बहुत गंभीर है। हमारी सार्थक चर्चा हुई और मैंने उन बिंदुओं को सामने रखा जो राधा के परिवार ने मेरे साथ साझा किए थे। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। समुदाय के सुझावों पर प्रकाश डालते हुए, गांधी ने इस मुद्दे के समाधान के लिए पर्याप्त उपायों की कमी पर ध्यान दिया। केवल दो वन चौकीदार हैं।

मदुरै पवित्र पहाड़ी मामलों की सुनवाई 4 फरवरी को होगी

नईदिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मदुरै जिले में थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी से संबंधित सभी मामलों को 4 फरवरी को सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। यह निर्णय मदुरै के निवासी कन्नन द्वारा दायर एक याचिका के बाद

आया है, जिसमें पशु बलि और भोजन परोसने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पहाड़ी के ऊपर स्थित सिकंदर बदुशा दरगाह में मांसाहारी भोजन मिलता है। याचिका में थिरुपरनकुंड्रम मंदिर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया गया, जिसे पंड्या युग के दौरान बनाया गया था। इसने मंदिर के दक्षिणी हिस्से में उमयंदर गुफा मंदिर और 11 पवित्र तालाबों की उपस्थिति पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि मंदिर परिसर के भीतर किसी भी प्रकार के पशु बलि या मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कन्नन की याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2024 में अनुष्ठानों और सांप्रदायिक दावतों के हिस्से के रूप में दरगाह पर कथित तौर पर बकरियों और मुर्गियों की बलि दी गई, जिससे सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के भक्तों को गहरी नाराजगी हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन

नईदिल्ली। उत्तराखंड की धार्मिक विरासत और जैव विविधता का झलक पेश करते रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस प्रतियोगिता के तहत 32 खेलों में लगभग 10 हजार खिलाड़ी पदक

जीतने के लिए चुनौती पेश करेंगे। खेल 14 फरवरी तक चलेंगे और देहरादून में मुख्य आयोजन स्थल सहित इस पहाड़ी राज्य के सात शहरों में स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। लगभग 450 स्वर्ण पदक और इतनी ही संख्या में रजत और कांस्य पदक दांव पर हैं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवभूमि आज युवा ऊर्जा से और दिव्य हो उठी है। बाबा केदार, बद्रीनाथ जी, मां गंगा के शुभाशीष के साथ आज नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने-कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। नेशनल गेम्स में इस बार भी कई देशी और पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है।

भारत के कंधों पर ही विश्व का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी : भागवत

कृष्णमोहन झा/

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गत 26 जनवरी को भारत के 76 वें गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत भिवंडी शहर में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में ध्वजारोहण किया । इस अवसर पर अपने भाषण में उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हमारे लिए गणतंत्र दिवस जश्न के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद रखने का अवसर भी है । संघ प्रमुख ने कहा कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत के बाहर विविधताओं के कारण झगड़े हो रहे हैं परन्तु विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हम विविधता को जीवन के स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखते हैं। भागवत ने अपने भाषण में इस बात को रेखांकित किया कि आपकी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं लेकिन आपको एक दूसरे के प्रति अच्छा होना चाहिए। एकजुटता ही सद्भाव से जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर आपका परिवार दुखी है तो आप खुश नहीं रह सकते । इस लेकिन तरह ,लेकिन अगर आपके शहर में कोई परेशानी है तो आपके शहर का कोई परिवार खुश नहीं रह सकता ।

संघ प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि आज सारा विश्व भारत से नेतृत्व की अपेक्षा कर रहा है। भारत को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए बहुत से लोगों ने समर्पित होकर कार्य किया है। समर्पण की भावना के साथ विश्व का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर है। संघ प्रमुख ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पण की भावना से ही हम भारत को विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित कर पाएंगे और भावी पीढ़ी इसी मार्ग पर चलकर भारत को विश्व में गौरवशाली बनाएगी।

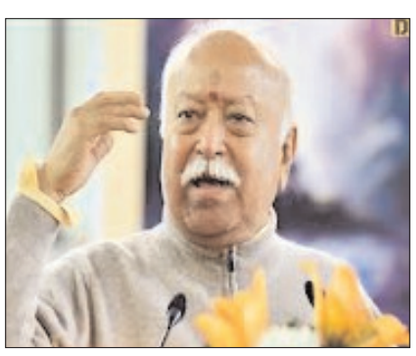

संघ प्रमुख ने समर्पण के साथ ज्ञान की आवश्यकता को प्रतिपादित करने के लिए चांवल पकाने की प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए कहा कि चांवल पकाने के लिए चांवल , पानी और ताप की आवश्यकता होती है। आपको चावल पकाने की विधि मालूम है तो आपको पकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप कच्चा चावल खाकर और पानी पीकर घंटों धूप में खड़े रहेंगे तब भी चावल पकाना संभव नहीं होगा। इसीलिए समर्पण के साथ ज्ञान भी जरूरी है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य केवल परेशानी लाता है ।संघ प्रमुख ने दैनिक जीवन में समर्पण के साथ भरोसे को महत्वपूर्ण बताते हुए एक और सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक होटल में जाकर केवल पानी पीते हैं और वहां से चले जाते हैं तो आपको अपमानित होना पड़ सकता है परन्तु अगर आप किसी घर में जाकर पानी मांगेंगे तो आपको खाने की किसी वस्तु के साथ पानी दिया जाएगा । यह समर्पण के भरोसे का परिचायक है जिसका अच्छा फल मिलता है। मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में बंधुत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया। बंधुभाव ही असली धर्म है।

पद्मश्री अन्ना साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी द्वारा 76 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से दिए गए अपने उद्बोधन में सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि आज भारत आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है जिससे उसकी सामरिक शक्ति भी बढ रही है। यह सब अन्ना साहेब जाधव जैसे पूर्वजों के त्यागपूर्ण जीवन के कारण ही संभव हो पाया है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद तीनों रंगों का अपना अलग महत्व है जिसमें नारंगी रंग बलिदान और समर्पण , सफेद रंग शुचिता और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित अशोक चक्र आपसी भाईचारे और बंधुत्व का प्रतीक है,यह सामाजिक समरसता और सद्भाव का संदेश देता है। भिवंडी में संघ प्रमुख के मुख्य आतिथ्य में संपन्न गणतंत्र दिवस समारोह एक ऐसा यादगार आयोजन था जिसमें विद्यार्थियों और उपस्थित गणमान्य जनों के मन-मस्तिष्क पर संघ प्रमुख के सारगर्भित उद्बोधन ने गहरी छाप छोड़ी। समारोह में पद्मश्री अन्ना हजारे भारतीय समाज उन्नति मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।

चिरमिरी नगर निगम में बगावती बिगुल, विनय जायसवाल के लिए कार्यकर्ता असंतुष्ट

■ कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 में चिरमिरी नगर निगम में कांग्रेस के अंदर बागवती सुर दिखाई दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह चिरमिरी नगर निगम में महापौर प्रत्याशी के नाम को लेकर है। चिरमिरी में कांग्रेस ने महापौर का प्रत्याशी पूर्व विधायक विनय जायसवाल को बनाया है।जिनकी पत्नी कंचन जायसवाल इससे पहले महापौर थीं। जैसे ही विनय जायसवाल के नाम का ऐलान हुआ,वैसे ही निगम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टिकट की आंस लगाए दावेदारों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।

चिरमिरी निगम की बात करें तो पार्टी की कार्यकर्ता रेहाना नियाजी और अन्य महिला नेताओं ने पार्षद और मेयर प्रत्याशी के टिकट वितरण पर सवाल उठाए।रेहाना ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता 25 साल से झंडा उठाए खड़ा रहता है।लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो बागी लोगों को पद बांट दिया जाता है। चिरमिरी में जिस तरह से मेयर का टिकट बांटा गया है उसे देखकर यही लगता है कि कहीं ना

कहीं ये पैसे देकर खरीदा गया टिकट है। पहले विधायक ने अपने पत्नी को महापौर बनाया।इसके बाद जब दोबारा निगम के चुनाव हुए तो खुद दावेदार बन गए।ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है। चिरमिरी नगर निगम का नाम बदलकर जायसवाल नगर कर देना चाहिए।

रेहाना नियाजी ने कहा मुझे भी वार्ड पार्षद पद के लिए दावेदारी का मौका मिला था। लेकिन मेयर पद के लिए जो निर्णय लिया गया, उसमें पारदर्शिता की कमी है। ऐसा लग रहा है कि चिरमिरी कांग्रेस में अब लोकतंत्र की जगह परिवारवाद ने ले ली है।

चिरमिरी में सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब पार्टी के उठाए गए कदम से नाराज दिख रहे हैं।नेताओं को उम्मीद थी कि इस बार टिकट वितरण में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी।लेकिन ऐसा नहीं हुआ।विनय जायसवाल का नाम सामने आने के बाद वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के फैसले पर आपत्ति जताई।कांग्रेस का ये चेहरा पहली बार सामने नहीं आया है।पार्टी में गुटबाजी और चहेतों को बढ़ावा देने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। वरुण शर्मा जो 1974 से कांग्रेस से जुड़े हैं।उन्होंने भी पार्टी के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है।साथ ही साथ फैसला नहीं बदलने पर आगामी निकाय चुनाव में मजा चखाने की धमकी दी है।

वरिष्ठ नेता कांग्रेस वरुण शर्मा ने कहा यह पहली बार है कि पार्टी ने संगठन की बजाय व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दी है।कांग्रेस पार्टी ने जीतने वाले प्रत्याशी की टिकट काटकर ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया है जो पार्षद प्रत्याशी के तौर पर पांच वोट नहीं पा सकते हैं।एक ही परिवार में डबल-डबल महापौर की नियुक्ति करना ये कहां तक जायज है।आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी।महंत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं,लेकिन उन्होंने हमारी जुबान बंद रखकर विधायक के लिए दूसरों का टिकट काट दिया।जिससे हम असंतुष्ट होकर पार्टी को अलविदा कहते हैं।

वरिष्ठ नेता कांग्रेस ओमप्रकाश गुप्ता ने कहा पार्टी में एक ही परिवार को बार-बार टिकट दिया जाना अनुचित है। इस बार मैं चुनाव में किसी भी तरह का प्रचार नहीं करूंगा और ना ही पार्टी का साथ दूंगा। कांग्रेस ने केवल अपने चहेतों को महत्व दिया है, जबकि समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है।जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है।

वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलदेव दास ने विनय जायसवाल को टिकट दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बलदेव दास ने कहा कि पार्टी ने चुनाव को लेकर जो नियम बनाए थे, उसके अनुसार ब्लॉक स्तर पर दावेदारों की सूची तैयार होनी थी। लेकिन विनय जायसवाल का नाम इस सूची में नहीं था। बलदेव दास ने कहा यह निर्णय संगठन की भावनाओं के खिलाफ है। इससे मैं आहत हूं। मैंने अपना इस्तीफा जिला कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया है।आगामी चुनाव में मैं पार्टी के लिए किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करुंगा।

वहीं दूसरी ओर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने विनय जायसवाल को मेयर कैंडिडेट बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा विनय जायसवाल को टिकट जीतने की क्षमता और उनके अनुभव को देखते हुए दिया गया है। हमने हर छोटे-बड़े कार्यकर्ता की भावनाओं का ध्यान रखा है। यह फैसला सामूहिक रूप से लिया गया है।

चिरमिरी में कांग्रेस के अंदर खलबली साफ देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि पार्टी इस असंतोष को कैसे शांत करेगी।क्योंकि यदि कार्यकर्ता ही चुनाव में पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो कांग्रेस के लिए चुनावी वैतरणी पार करना मुश्किल होगा। परिवारवाद और पैसों के लेनदेन के आरोपों के बाद अब तक विनय जायसवाल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।लेकिन एक बात साफ है कि नाराज कार्यकर्ताओं को यदि नहीं मनाया गया तो आने वाले दिनों में चिरमिरी में कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है।

मनेंद्रगढ़ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं प्रभा पटेल : महंत

मनेंद्रगढ चिरमिरी भरतपुर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मंगलवार को मनेंद्रगढ़ पहुंचे। महंत ने मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा पटेल से उनके घर पर मुलाकात की। मीडिया से चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने निकाय और पंचायत चुनावों में जीत का दावा किया। चरणदास महंत के साथ प्रभा पटेल के घर पूर्व कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। महंत की मौजूदगी में प्रभा पटेल को जिताने की रणनीति बनी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि हम एमसीबी की सभी 6 सीटें जीतना चाहते हैं।

महंत ने कहा कि पार्टी की कोशिश है कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराए। चरणदास महंत ने कहा कि इस बार पार्टी आलाकमान ने बड़े सोच समझ के साथ उम्मीदवारों का चयन किया है। मौका उनको ही मिला है जो अपनी सीट जीत सकते हैं। महंत ने भरोसा जताया कि पार्टी अपनी मजबूत संगठन शक्ति और रणनीति की बदौलत इस बार मजबूत प्रदर्शन करेगी। ब्लॉक अध्यक्ष के इस्तीफे को महंत ने छोटी मोटी घटना बताया। चरणदास महंत ने कहा पार्टी में इस तरह की छोटी मोटी नाराजगी होती रहती है। डॉक्टर ने अपना नामांकन भर दिया है जो भी असंतोष होगा उसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

गीदम नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आमने सामने दो भाई

दंतेवाड़ा। जिले में गीदम नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। इसकी वजह है कि यहां दो भाई आमने सामने चुनावी दंगल में खड़े हैं। एक कांग्रेस प्रत्याशी है तो दूसरा भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में खड़ा है।

गीदम नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे दोनों भाइयों का नाम रविश सुराना और रजनीश सुराना है। दोनों चचेरे भाई है। रविश सुराना कांग्रेस से तो रजनीश सुरना भाजपा से भाग्य आजमा रहे हैं। दोनों भाई बचपन में साथ मिलकर कभी साइकिल रेस तो कभी रेसिंग कर हार जीत का लड़ाई लड़ते थे। अब चुनाव में दोनों भाई हार जीत का दांव लगा रहे हैं।

गीदम नगर पंचायत सीट जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। क्योंकि, भाजपा सिटिंग रूरूचैतराम अटामी, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ममता गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन विश्वकर्मा, विजय तिवारी जैसे दिग्गज नेताओं का गढ़ गीदम रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विमल सुराना, शकील रिजवी जैसे बड़े लीडर्स भी यहीं रहते हैं। ऐसे में रविश और रजनीश के साथ-साथ इन नेताओं की भी साख दांव पर लगी है।

रविश सुराना की मां राधा सुराना वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। बड़े भाई मनीष सुराना जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे हैं। जबकि, भाभी हारम पारा की सरपंच हैं। वहीं रजनीश गीदम व्यापारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अब नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं।

कांग्रेस प्रत्याशी रविश सुराना गीदम नगर

पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। वे चुनाव हार गए थे लेकिन कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ दिया था। वे तीसरे पोजिशन पर थे। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस ने उनकी पत्नी साक्षी रविश सुराना को चुनावी मैदान में उतारा था। पार्षदों का समर्थन पाकर साक्षी अध्यक्ष बनीं। वहीं इस बार सामान्य सीट आई तो कांग्रेस ने रविश पर भरोसा जताया। वे दोबारा भाग्य आजमाने चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। इनका सीधा मुकाबला खुद के भाई से है।

दोनों भाइयों के बीच मुकाबले में परिवार का वोट बंटेगा। जिस पर लोगों की खास नजर रहेगी।गीदम नगर पंचायत क्षेत्र में सुराना फैमिली और समाज के वोटर्स काफी ज्यादा है। एक ही परिवार से अलग-अलग पार्टी से दो कैंडिडेट खड़े है जिससे समाज और परिवार के वोट भी बंटेंगे। परिवार और समाज के वोटर्स के साथ ही दोनों भाई अन्य वर्गों के वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं। हालांकि दोनों भाइयों की छवि नगर में अच्छी है।

छुईखदान नपं में पूर्व अध्यक्ष गिरीराज पत्नी के साथ कांग्रेस में शामिल

नम्रता को मिला टिकट

राजनांदगांव। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का दौर अभी शुरु नहीं हुआ लेकिन टिकट के दावेदार जोरशोर से प्रचार प्रसार करना शुरु कर दिया और कई उम्मीदवार पार्टी छोड़कर भाजपा और कांग्रेस में शामिल हो रहे है। इसी बीच खैरागढ़ जिले के छुईखदान नगर पंचायत में उलटफेर हुआर है जिसमें पूर्व अध्यक्ष गिरीराज वैष्णव ने पत्नी नम्रतादास वैष्णव और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया।

कांग्रेस ने तत्काल नम्रता को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। गिरीराज अपनी पत्नी की टिकट के लिए भाजपा से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी ने राजनांदगांव जिले के कद्दावर नेता खूबचंद पारख की बेटी शीतल जैन को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस फैसले से आहत गिरीराज ने कांग्रेस का रुख किया। अब छुईखदान में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए दोनों महिलाओं के बीच तगड़ा मुकाबला होगा।

बताया जाता हैं कि गिरीराज लगातार 10 वर्षों तक नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में वह भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। खैरागढ़ जिले में हुए इस उलटफेर से भाजपा नेताओं की पैरो तले जमीन खिसक गई। गिरीराज एक बड़े चेहरे के रूप में शुमार किए जाते हैं। कांग्रेस प्रवेश से पहले गिरीराज ने छुईखदान इलाके के कई पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर राजधानी रायपुर का रुख किया। वहां उन्होंने पूर्व सीएम के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ली। बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से भी मुलाकात की।

तखतपुर से भाजपा और कांग्रेस ने उतारे सशक्त महिला प्रत्याशी

तखतपुर। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियों के अखाड़े तैयार हो चुके हैं। तखतपुर नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस ने दमदार महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इन दोनों प्रत्याशियों की वजह से ठंड के मौसम में भी राजनीतिक गर्माहट बढ़ने के साथ ही सीट हाई प्रोफाइल हो गई है।

एक तरफ भाजपा ने वंदना सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। जो कि तखतपुर विधायक धर्मजीत की बेहद करीबी है। और वर्तमान में नगर पालिका की उपाध्यक्ष है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक जगजीत सिंह मक्कड़ की बहू और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आत्मजीत की धर्मपत्नी रविंदर (पूजा) मक्कड़ को मैदान में उतार कर इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है।

एक तरफ भाजपा अपने महतारी वंदन योजना और डबल इंजन की सरकार का हवाला देते हुए विकास के दावे को लेकर मैदान में उतरने जा रही है। वंदना ने बताया कि कांग्रेस के 5 साल में विकास कार्य नहीं हुए हैं, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, यहां विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहा है।

वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी रविंदर (पूजा) मक्कड़ अपने ससुर विधायक जगजीत सिंह मक्कड़ और सास पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र कौर मक्कड़ के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और दोबारा तखतपुर को विकसित तखतपुर बनाने का दावा करते हुए जनता के दरबार में पहुंचने की तैयारी है। पूजा मक्कड़

ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि तखतपुर धूल का शहर बन चुका है। उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार आई तो तखतपुर नगर धूल मुक्त होगा। विकास के इबारत गढ़े जाएंगे, लेकिन धूल की समस्या और बढ़ गई। नगर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय की कमी हैं, जिनके कारण उनको प्रसाधन के लिए भटकना पड़ता है। साफ-सफाई जैसे कई अनेक समस्याएं बनी हुई है।इस तरह से दोनों ही पार्टियों ने दमदार महिला प्रत्याशी उतारकर अपनी-अपनी ओर से संदेश दे दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि जनता के दरबार में इन दोनों प्रत्याशियों का भविष्य क्या होगा। भाजपा अपना कमल खिला पाएगी या कांग्रेस का हाथ तखतपुर की जनता मजबूत करेगी।

तखतपुर की प्रमुख समस्याएं- 1. सड़क में धूल का गुबार। 2. बढ़ता ट्रैफिक समस्या। 3. महिला प्रसाधन की समस्या। 4. मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण से सदर बाजार और जनकपुर रोड पर चलना दूभर। 5. शहर के गंदे पानी का संगम बना मनियारी नदी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बंदरचुंवा चर्च हादसा, छत की सेंट्रिंग गिरने से छह घायल

जशपुर। जशपुर जिले के बंदरचुंवा स्थित नार्थ वेस्टर्न जीईएल चर्च में छत की ढलाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मंगलवार को छत की सेंट्रिंग गिरने से छह मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में ठेकेदार शकील खान (अंबिकापुर निवासी) भी शामिल है, जिनका पैर टूट गया है। अन्य मजदूरों के कमर और हाथ-पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुए हैं। घटना के समय छत पर करीब 50 मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि, हादसे में सबसे ज्यादा चोटें उन मजदूरों को आईं, जो नीचे काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी सैहुन टोप्पो ने बताया कि घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से कुनकुरी के निजी अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद 108 एंबुलेंस घायलों को कुनकुरी के सरकारी अस्पताल ले गई, लेकिन उन्हें इलाज के लिए जशपुर रेफर कर दिया गया। दोकड़ा पुलिस चौकी प्रभारी अशोक यादव ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हादसे की जांच जारी है। छत की सेंट्रिंग गिरने का कारण और हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

सिरगिट्टी में निर्माणाधीन भवन की छत गिरने से हादसा

बिलासपुर। सिरगिट्टी क्षेत्र में ढलाई के समय छत गिर गई। जिससे मलबे में महिला सहित कुछ मजदूर दब गये। हादसे में इलाके में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में मलबा हटाकर मजदूरों को अस्पताल मे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल, सिरगिट्टी थाना प्रभारी ने बताया कि सेक्टर ए में एक फैक्टरी का भवन बन रहा है। सोमवार की शाम पहले तल की छत पर ढलाई चल रही थी। इसी दौरान करीबन शाम के समय छत भसक कर नीचे गिर गई। जिसमें नीचे में काम कर रहे मजदूर राजकुमारी, मोनू ध्रुव, अशोक साहू, दुर्गेश साहू मलबे में दब गए। मजदूरों के दबने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से पुलिस ने मलबा हटाकर नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला। उसके बाद चारों को तोरवा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल, उनकी स्थिती समान्य बताई जा रहा है। सिरगिट्टी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

रास्ता रोककर राहगीरों से लूटपाट, दो गिरफ्तार

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में रास्ता रोककर राहगीरों से लूटपाट दो आरोपी अमन कुमार साहू कोनी जिला बिलासपुर और सूरज कुमार घृतलहरें ग्राम अमोरा जांजगीर को गिरफ्तार करने में पुलिस की सफलता मिली है। वहीं लूट के लिए सामनों को बरामद किया गया है। लूट की घटना के अन्य आरोपियों की अभी तलाश जारी है। जानकारी अनुसार, 24 जनवरी 2025 की रात 8.20 बजे को बिलासपुर की रहने वाली युवती से नेशनल हाईवे 49 ग्राम अमरताल के गोदाम के पास उसकी एक्टिवा गाड़ी और एक आईफोन 15 दोनों की कीमत करीबन 1 लाख 85 हजार रुपए की अज्ञात बदमाशों ने लूट लिए थे। इसी तरह ग्राम किरारी निवासी नारद कश्यप की बाइक एचएफ डीलक्स और वीवो कंपनी का मोबाइल कीमत लगभग 60 हजार रुपये लूट लिए गए। लूटी हुई बाइक, एक्टिवा, आईफोन, वीवो कंपनी का मोबाइल सभी की कीमत कुल 2 लाख 40 हजार रुपये के सामनों को दोनों आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया है।

हजरत बाबा महबूब शाह दातार का 119 वां उर्स आज

कबीरधाम। कवर्धा के हजरत बाबा महबूब शाह दातार का 119वीं उर्स 29 जनवरी बुधवार को मनाया जा रहा है। उर्स के अवसर पर जिले में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने थाना कवर्धा में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम कवर्धा आकांक्षा नायक व डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने की। बैठक में मुस्लिम ट्रस्ट, दरगाह कमेटी और मोहल्ला कमेटियों के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न करना था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग पर सख्त नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी आयोजकों ने प्रशासन और पुलिस को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

साहसी बालक ने भालू से लड़कर बचाई पिता की जान

बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद जंगल वहां रहने वाले आदिवासियों के लिए जीविकोपार्जन का बड़ा सहारा है। आदिवासी जंगल से ही अपने खाने पीने और रहने के लिए कई चीजें हासिल करते हैं। लेकिन इस दौरान कई बार उनकी जान जोखिम में भी पड़ जाती है। जंगल में मौजूद वन्य प्राणियों से उनका सीधा सामना हो जाता है। सोमवार को दंतेवाड़ा में ऐसा ही हुआ। जहां बांस लेने जंगल गए पिता पुत्र का सामना भालू से हो गया। लेकिन 10 साल का बच्चा बिना डरे भालू के सामने चला गया और अपने पिता की जान बचाई। वंजाराम नेताम, पांचवीं में पढ़ने वाले अपने 10 साल के बेटे दीपक के साथ घने जंगल के बीच स्थित हांदावाड़ा जलप्रपात के पास गया था। पिता पुत्र बांस काटने के लिए जंगल के अंदर पहुंचे थे। तभी अचानक एक जंगली भालू ने वंजाराम नेताम पर हमला कर दिया। भालू के हमले से वंजाराम लहूलुहान हो गया। पिता की जान खतरे में देख दीपक डंडे के सहारे भालू से भिड़ गया।

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

■ ओबीसी आरक्षण मामला : हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

बिलासपुर। ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने सूरजपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर डिवीजन बेंच में लंबी कानूनी बहस हुई। दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विधि संगत निर्णय लेते हुए मेरिट बेस पर याचिका को खारिज किया।

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बैंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शक्तिराज सिन्हा ने राज्य शासन द्वारा ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड।) की उपधारा (03) को विलोपित किए जाने और बीते वर्ष 3 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़

पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2024 को लेकर अपना पक्ष रखा।

राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने शासन का पक्ष रखते हुए इस मामले में नए अध्यादेश 23 जनवरी 2025 को जारी होने की बात कही। इसे सरकार की ओर से बजट सत्र में विधानसभा पटल में रखने की जानकारी दी। वहीं कोर्ट में संवैधानिक रूप से इस अध्यादेश को पारित होने को लेकर अनुच्छेद 213(2) के तहत राज्यपाल से सहमति पारित होने और विधानसभा के समक्ष पुन: समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले निरनुमोदन का प्रस्ताव पारित करने को लेकर पक्ष रखा।

इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा ने अपनी याचिका में कही बातों को दोहरा और आरक्षण संबंधी संशोधन के नियमों को लेकर पूर्व अध्यादेश पर अपनी बात रखी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश को लेकर दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया। इस पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अपनी दलील रखी। वहीं कोर्ट ने इस मामले में उन निर्णयों के संदर्भ से संबंध नहीं देखते हुए विधि संगत निर्णय लिया।

जानिए पूरा मामला- हाईकोर्ट में जिला पंचायत सूरजपुर के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, पांचवी अनुसूची में शामिल जिलों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड।) की उपधारा (03) को लोप करने के लिए पिछले साल 3 दिसंबर को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2024 को लाया। भारत के संविधान की अनुच्छेद 213 में निहित प्रावधान के तहत कोई भी अध्यादेश अधिकतम छह माह की अवधि तक ही क्रियाशील होता है अथवा विधानसभा के आगामी सत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव पारित कर अधिनियम का रूप दिलाना होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने गंभीर चूक की है। अध्यादेश जारी होने के बाद 16 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक आहूत छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं कराते हुए मात्र विधानसभा के पटल पर रखा गया है। इसके कारण अध्यादेश वर्तमान में विधिशून्य/औचित्यविहीन बताया गया। ऐसी स्थिति में वर्तमान में उक्त संशोधन के आधार छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम (5) में दिनांक 24 दिसंबर 2024 को किया गया संशोधन पूर्णत: अवैधानिक है, लेकिन इस पूरे मामले में 20 जनवरी को सुनवाई हुई और सरकार को कैबिनेट में पारित करने के संवैधानिक अधिकार के तहत 6 सप्ताह का समय दिया।

एसईसीएल ने 281 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन रिमूवल किया हासिल

बिलासपुर। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने 281 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन रिमूवल (ओबीआर) का महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने अपने प्रो-राटा लक्ष्य का 105 प्रतिशत पूरा करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 19.82 मिलियन क्यूबिक मीटर (7.58 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की है। एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डॉ. प्रेम सागर मिश्रा ने विश्वास जताते हुए कहा कि एसईसीएल प्रतिदिन औसतन 13 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक ओबीआर कर रहा है, जिससे उसके संचालन में अभूतपूर्व गति आई है। कंपनी को उम्मीद है कि यह न केवल चालू वित्तीय वर्ष का वार्षिक ओबीआर लक्ष्य हासिल करेगा बल्कि अतिरिक्त 40-45 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबीआर भी हटाने में सफल रहेगा। एसईसीएल ने अपने मेगाप्रोजेक्ट्स में पर्यावरण के अनुकूल ब्लास्ट-फ्री वर्टिकल रिपर तकनीक का उपयोग बढ़ाया है, जिससे ओबीआर कार्यों में और अधिक दक्षता आई है। कंपनी ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाते हुए वर्ष 2024 में 880 से अधिक भू-स्वामियों को रोजगार प्रदान किया है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल डेका से नव नियुक्त सचिव डॉ. प्रसन्ना ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल के नव नियुक्त सचिव डॉ. श्री सी. आर प्रसन्ना ने भेंट की। राज्यपाल ने उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं। नव नियुक्त सचिव डॉ. श्री सी. आर प्रसन्ना ने आज राजभवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2006 बैच के अधिकारी हैं। उनके पास सहकारिता विभाग का भी कार्यभार है।

शहर कांग्रेस सचिव मनोज ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन और कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को देर रात अपनी पार्षदों की सूची जारी की। टिकट की चाह रखने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार इससे नाराज है तो कई खुश भी है क्योंकि उन्हें पहली बार पार्षद चुनाव लडने् का मौका मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर इस्तीफों का दौर भी शुरु हो गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 60 के रहने वाले मनोज पाल ने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देते हुए अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज को भेज दिया है। पाल वर्तमान में शहर कांग्रेस के सचिव और प्रदेश महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस असंगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री थे।

लंबे समय से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों पर बड़ी कार्यवाही, हुए सेवा मुक्त

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 27 चिकित्सा अधिकारियो व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही 21 चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए है। विदित हो कि चिकित्सा अधिकारियों व विशेषज्ञ चिकित्सकों को अपने कर्तव्यस्थल से लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हुए शासन के मूलभूत नियम और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम का उल्लंघन किया गया था। अनुपस्थित अधिकारियों व चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी करके अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया था। सुनवाई में उपस्थित चिकित्सा अधिकारियों/ विशेषज्ञ चिकित्सकों के पक्ष को सुना गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए चिकित्सा अधिकारियो व विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं।

अग्रवाल सभा के रक्तदान शिविर में हुआ 126 यूनिट ब्लड डोनेट

रायपुर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अग्रवाल सभा के द्वारा मरीन ड्राइव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जहां शाम 5 बजे तक 126 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। सभी डोनर को उपहार के रुप में पावर बैंक दिया गया ताकि वे अपने मोबाइल की बेटरी खत्म हो जाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकें। डोनेट किया ब्लड मेकाहारा के मॉडल ब्लड बैंक को प्रदान किया गया है ताकि मेकाहारा में आए जरुरतमंद मरीजों को निशुल्क प्रदान किया जा सके। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, मनमोहन अग्रवाल, रक्तदान संयोजक सुधीर अग्रवाल, सदभावना ग्रुप, होरा, आरोग्य हॉस्पिटल की टीम, कोषाध्यक्ष प्रेम अग्रवाल, संगठन मंत्री योगी अग्रवाल, मोहल्ले के संयोजक अशोक गोयल, सुजीत अग्रवाल, बॉबी जैन, बिंदिया अग्रवाल, अंजू अग्रवाल, प्रचार प्रसार मंत्री ज्योति अग्रवाल, युवती मंडल से खुशबू डालमिया, महक डालमिया के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 4 अधिकारी गिरफ्तार

रायपुर। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 4

अधिकारियों को रेंज साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, सभी म्यूल बैंक अकाउंट प्रकरण में बैंक के ड्यू डीलीजेन्स, केवाईसी नॉर्म्स का पालन नहीं करने, बैंक खाता खोलने के बदले ब्रोकरों से रकम प्राप्त करने, बैंक से भी इनसेंटिव लेते रहे। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 72 फ्राड आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय हैं कि आईजी अमरेश मिश्रा की निगरानी में 20 से अधिक टीमें बनाकर 50 से अधिक स्थानों पर रेड किया और म्यूल बैंक खाता धारक/ब्रोकर कुल 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ व तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों से कनेक्ट होने पर थाना सिविल लाइन धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111, 3(5) बी एन एस में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शाखा सिविल लाइन के 4 बैंक अधिकारियों गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बैंक अधिकारियें में शुभम सिंह ठाकुर 27 मठपारा दुधाधारी मंदिर रोड वार्ड न. 64 टिकरापारा, हिमांशु शर्मा 26 वार्ड क्रमांक 10 आरंग, सुमित दीक्षित 28 शंकर नगर श्रीराम नगर फेस 2 म.न. ए 1 थाना खम्हारडीह रायपुर, अनुपम शुक्ला 23 प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 02 पटेल पारा पुरानी बस्ती रायपुर शामिल है।

रायपुर को एक नयी पहचान दिलाकर स्वच्छ और विकसित राजधानी बनाएंगे : मीनल चौबे

महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने नामांकन पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट कर आशीर्वाद लिया

रायपुर। राजधानी रायपुर से भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे ने आज सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत, रायपुर दक्षिण के विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर उत्तर के विधायक सुनील सोनी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नगरीय निकाय और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनमें चुनाव होने जा रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे और 70 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। महापौर प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे को नगर निगम में पार्षद सहित नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का लंबा अनुभव है इसका लाभ अवश्य मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम सहित, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं त्रि स्तरीय पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त होगी। त्रि स्तरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। मोदी जी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने के कारण प्रदेश भर में

भाजपा के प्रति विश्वास का वातावरण है। इसी विश्वास की बदौलत हमें इस चुनाव में भी ऐतिहासिक जनादेश मिलेगा।

भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुन-चुन कर कर्मठ एवं योग्य ऊर्जावान प्रत्याशियों को उतारा है। मीनल जी भी अनुभवी और योग्य नेत्री हैं। मीनल चौबे एक बेहतर महापौर रायपुर के लिए साबित होंगी। पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा प्रत्याशी बड़ी संख्या में चुन कर आयेंगे।सभी प्रत्याशियों को फिर से शुभकामनाएं हैं।

भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि रायपुर की जनता ने नगर निगम में तीन बार कांग्रेस का कार्यकाल देखा है भ्रष्टाचार और कुशासन का पर्याय बन कर रह गए थे। इस बार जनता विकास की संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी में देख रही है मोदी जी की गारंटी पूरी हुई यह इस बात का प्रमाण है निश्चित तौर पर जनादेश भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एक वर्ष की उपलब्धि लेकर जनता के बीच जाएंगे। राज्य सरकार के साथ- साथ नगरीय निकाय में भी मिलकर काम करेंगे और स्वच्छ और विकसित रायपुर बनाकर एक नयी पहचान दिलाएंगे।

बृजमोहन-मूणत सम्हालेंगे रायपुर की कमान, नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव संचालकों की नियुक्ति

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष किरणदेव सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए चुनाव संचालक, सह-संचालक व समन्वयकों की नियुक्ति की। रायपुर की कमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक राजेश मूणत को सौंपी गई है।

रायपुर - बृजमोहन अग्रवाल - राजेश मूणत, समन्वयक - चंद्रशेखर साहू, सच्चिदानंद उपासने , श्रीचंद सुंदरानी । **बिलासपुर** - अमर अग्रवाल - धर्मजीत सिंह, समन्वयक - रामदेव कुमावत, किशोर राय। **दुर्ग** - विजय शर्मा, गजेन्द्र यादव, राजीव अग्रवाल, समन्वयक - श्रीमती उषा टावरी, कांतिलाल बोथरा। **कोरबा** - लखन लाल देवांगन, विकास रंजन महतो, समन्वयक - ननकी राम कंवर, जोगेश लाम्बा। **अम्बिकापुर** - राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज, प्रशांत त्रिपाठी, समन्वयक - कमलभान सिंह, कर्ताराम अग्रवाल । **चिरमिरी** - श्याम बिहारी जायसवाल , भईया लाल रजवाड़े, समन्वयक - अनिल केशरवानी, प्रेमकांत झा। **धमतरी** - अजय चंद्राकर , राजेन्द्र शर्मा, समन्वयक - इंदर चोपड़ा, कंजलाल देवांगन, निर्मल बरड़िया। **राजनांदगांव** - अभिषेक सिंह, संतोष अग्रवाल, समन्वयक - अशोक शर्मा, खूबचंद पारख, संतोष बाफना। **जगदलपुर** - केदार कश्यप, शरद अवस्थी, श्रीनिवास राव मही, समन्वयक - राजाराम तोड़ेम। **रायगढ़** - ओ.पी. चौधरी, विजय अग्रवाल, समन्वयक - गुरुपाल सिंह भल्ला, गौतम अग्रवाल।

चुनावी माहौल में शराब तस्करी का पर्दाफाश

सब्जी की आड़ में एमपी से छत्तीसगढ़ ला रहे थे अवैध शराब, पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करों को धरदबोचा

खैरागढ़। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे अपराधी अपने मंसूबों को पूरा करने के नए-नए तरीके आजमा रहे हैं। डोंगरगढ़ और बाग नदी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के दो बड़े मामलों का भंडाफोड़ किया है। सब्जी ढोने वाले वाहनों की आड़ में लाखों रुपए की शराब मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने तस्करों के इन मंसूबों को नाकाम कर दिया। पुलिस ने लाखों की शराब के साथ अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है।

डोंगरगढ़ पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को अवैध शराब तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सब्जी लाने वाले वाहनों में शराब छिपाकर मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में तस्करी की जा रही है। ग्राम कुम्हड़ाटोला मार्ग पर नाकाबंदी

कर पुलिस ने दो वाहनों यौधा डीआई और विस्टा कार को रोका। जब गाड़ियों की तलाशी ली तो 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हिस्की और 10 पेटी देशी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कुल मात्रा 405 लीटर और कीमत 2,36,250 रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही जब्त वाहनों, पांच मोबाइल फोन और अन्य सामग्रियों की कुल कीमत 14,62,250 रुपए है। पुलिस ने पांच अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम राजेश तागड़े, ईश्वर साहू, रौवन चंद्राकर, सोहेल मिन्नी, और ऋषिकेश हटिले हैं। इन सभी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

बागनदी पुलिस ने भी शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है। देवरी से राजनांदगांव की ओर आ रही एक पिकअप वाहन (एमएच-40-सीडी-2629) चिरचारी चेक पोस्ट पर लगे एमसीपी से बचने की कोशिश में ट्रक से टकरा गई। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें पत्तागोभी की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई 196 बोतल शराब बरामद हुई। शराब में रॉयल स्टेज, रॉयल चैलेंज, मैकडॉवेल नंबर 1 और ब्लेंडर प्राइड ब्रांड की बोतलें शामिल थीं। कुल 147 बल्क लीटर शराब की कीमत 2,36,595 रुपए आंकी गई है। जब्त वाहन समेत कुल संपत्ति 10,36,595 रुपए है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

डोंगरगढ़ टीआई जितेंद्र वर्मा ने बताया कि चुनावी माहौल में आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते पुलिस अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। जिलेभर में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डोंगरगढ़ और बाग नदी पुलिस की इन कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि तस्करों के नए-नए तरीके भी कानून की पकड़ से नहीं बच सकते। चुनावों में शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुलिस की यह सतर्कता बेहद महत्वपूर्ण है।

स्कूटी में सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचीं दीप्ति दुबे

रायपुर। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस महापौर पद की प्रत्याशी दीप्ति दुबे आज बिना किसी ताम-झाम के स्कूटी पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंची। न कोई रैली, न कोई शक्ति प्रदर्शन।

इस पर कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने कहा कि आज स्कूटी से हेलमेट पहन के आने का उद्देश्य यही के हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करें। आज हमने नामांकन जमा किया है। अब मैं लोगों के बीच में भी जाऊंगी। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।

इसके पहले कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस भवन गांधी मैदान से रैली निकालने की योजना थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। स्थल पर कार्यकर्ता इंतज़ार करते रहे। नामांकन दाखिल करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, रायपुर शहर ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे और पूर्व निगम सभापति प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे।

रायपुर में 15 साल तक हर वर्ग के लिए काम करने का मिलेगा फायदा : भूपेश

- **कांग्रेस में टिकट विवाद पर सिंहदेव बोले- नाराज नेताओं को मना लेंगे**

रायपुर। नगर निगम रायपुर के कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने आज नामांकन जमा किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमने पूरे नगरीय निकाय में बेहतर काम किया है। रायपुर में 15 साल तक हर वर्ग के लिए काम किया है, इसका फायदा मिलेगा। इस बार भी महापौर के लिए बेहतर प्रत्याशी का चयन किया है।

नेताओं-कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर बघेल ने कहा, कही-कही नाराजगी है, उन्हें मना लेंगे। नगरीय निकाय क्षेत्र में साय सरकार में एक ढेला काम नहीं हुआ है। इस बार भी कांग्रेस की जीत निश्चित है। भाजपा ने कांग्रेस में टिकट के लिए लेन-देन का आरोप लगाया है। इस पर भूपेश बघेल ने कहा, बिलासपुर में क्या इन्हें ओबीसी महिला नहीं मिला। भाजपा के लोग पैसे की भाषा समझते हैं, इसलिए पैसे की बात करते हैं।

कांग्रेस में टिकट विवाद पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, यह तो प्रक्रिया है। कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन उनको मना लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में 90 सीट है, जबकि नगर निगम रायपुर में अकेला 70 सीट है। इसमें सभी को खुश नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कुंभ पर दिए बयान को लेकर सिंहदेव ने कहा, यह संवेदनशील विषय है। इस पर उन्होंने अपना दृष्टिकोण बताया है। अब हर बात में सनातन की बात होती है। 72 साल की उम्र में मुझे भी लगता है अब सनातन समझना होगा। धर्म अलग है और कर्म अलग है। धर्म के साथ कर्म और मेहनत भी जरूरी है।

कौन होगा बिलासपुर का अगला महापौर?

रायपुर/बिलासपुर। नामांकन दाखिले की समयसीमा समाप्त से ठीक पहले भाजपा और कांग्रेस ने बिलासपुर नगर निगम के मेयर प्रत्याशियों की घोषणा की है। सभी अटकलों को खारिज करते हुए भाजपा ने प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रहीं पूजा विधानी को मौका दिया है, वहीं कांग्रेस ने सहकारी बैंक में रहते हुए पहचान बनाने वाले प्रमोद नायक को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही पार्टियों ने आधा दर्जन से अधिक दावेदार होने के बाद भी इन्हीं दो नामों पर भरोसा किया है। जाहिर है, पूजा अपनी पार्टी की महतारी वंदन योजना के साथ विकास का भरोसा दिलाने के लिए वोट मांगेंगी, तो प्रमोद नायक अपनी स्वच्छ छवि के साथ चुनाव मैदान में नायक बनने की कोशिश करेंगे। इस बीच टिकट बंटने के साथ ही टिकट से वंचित दावेदार और उनके समर्थकों ने संगठन के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरु कर दिया है।

ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक की महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक से रिश्तेदारी है। चर्चा इस बात की भी है कि किरणमयी नायक ने रायपुर से दावेदारी थी, इस कारण भी रायपुर और बिलासपुर का फैसला करने में विलंब हुआ। वहीं भाजपा ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रहे

अशोक विधानी की पत्नी पूजा विधानी को टिकट दिया है। पूजा खुद भी संगठन में दो दशक से सक्रिय रहते हुए विभिन्न पदों में रह चुकी हैं। भाजपा ने मेयर से लेकर सभी 70 वार्ड में पार्षद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी 27 जनवरी की देर शाम तक सभी 70 वार्डों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।

नामांकन पत्र जमा करने के पांचवे दिन तक नगर निगम चुनाव के महापौर के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इनमें प्रमोद कुमार नायक कांग्रेस, रेवती यादव शिव सेना, एल पदमजा विधानी बीजेपी, राजकुमार निषाद निर्दलीय एवं रमा नाविक निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। 27 जनवरी की स्थिति में बिलासपुर नगर निगम के मेयर पद की दावेदारी करने के लिए 10 दावेदारों ने नामांकन पत्र लिया है। 10 दावेदारों में से 4 महिलाएं हैं और 6 पुरूष हैं।

57 वर्षीय प्रमोद नायक ने एमकॉम की पढ़ाई की है। वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ कुर्मी चेतना मंच प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के महामंत्री रह चुके हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 54 वर्षीय पूजा विधानी ने एमए तक पढ़ाई की है। पूजा विधानी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी की पत्नी हैं। वे बीते दो दशक से शहर की राजनीति में सक्रिय रही हैं। 1996 से भाजपा के सक्रिय सदस्य रहीं, 1998 में पहली बार पार्षद भी बनी थीं। इसके अलावा पार्टी ने उन्होंने दो बार महिला मोर्चा अध्यक्ष व दो बार प्रदेश महामंत्री का दायित्व सौंपा था।

सोमवार को 100 से ज्यादा पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। पार्षद चुनाव के लिए अब तक 288 लोगों ने उम्मीदवारी की है। इसमें महिलाओं की संख्या 107 और पुरूषों की संख्या 181 है। 28 जनवरी को नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख थी। अंतिम दिन यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। मतदान 11 फरवरी को होगा।

टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस के असंतोष पर मुखर हुए भाजपा सांसद और विधायक

रायपुर। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ताओं के असंतोष को देखते हुए भाजपा के नेता मुखर हो गए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तो निकाय चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी कर दी है। वहीं विधायक सुनील सोनी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दर्द बयां किया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि असंतुष्टि ही कांग्रेस को डुबायेगी, और उनकी असंतुष्टि में ही बीजेपी का कमल फूल खिलेगा। टिकट खरीदी-बिक्री को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ऊपर स्तर तक पैसे पर पैसे से ही बात होती है, फिर ये तो निचले स्तर की बात है।

वहीं टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं की बगावत को लेकर दूसरी ओर विधायक सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस ने अंतिम समय तक कार्यकर्ताओं को रुलाया है। पैसों के नाम पर कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू बहाए हैं, और

फिर टिकट के लिए चक्कर कटवाए। कांग्रेस नेताओं को शर्म आना चाहिए।

कांग्रेस में टिकट खरीदी-बिक्री को लेकर विधायक ने कहा कि इनके पूर्व विधायक ही बता रहे हैं कि टिकट खरीदा और बेचा जाता है। छोटे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा करेंगे तो जनता दूर होगी ही। आने वाले समय में कार्यकर्ता भी दूर हो जाएंगे।

कांग्रेस ने रायपुर निगम में थोक में काटे पार्षदों के टिकट

कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम में थोक में चुने हुए पार्षदों के टिकट काटकर दूसरे को दे दिया है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस के भीतर टूट-फूट शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर भाजपा के नेता कांग्रेस में मचे घमासान पर तंज कसने लगे हैं।

दरअसल, कांग्रेस ने रायपुर नगर निगम में थोक में सिटिंग पार्षदों के टिकट काटे हैं। इनमें वार्ड 27 से पार्षद सुरेश चन्नावार, वार्ड 28 से हरदीप सिंह होरा 'बंटी', वार्ड 29 से पुरुषोत्तम चंद्र बेहरा, वार्ड 35 से आकाश तिवारी, वार्ड 36 से अनवर हुसैन, वार्ड 37 से रितेश त्रिपाठी, वार्ड 40 से सीनियर पार्षद ज्ञानेश शर्मा और वार्ड 62 से पार्षद समीर अखूतर का टिकट कटा है। वहीं महापौर और वार्ड 46 के पार्षद एजाज़ ढेबर को वार्ड 57 से टिकट दिया गया है।

व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए राजनीति करते हैं कांग्रेसी: श्रीवास्तव

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस में इस्तीफों के दौर पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताधारी पार्टी है, जहां हर एक नेता अपने आदमी को बैठना चाहता है। कांग्रेस का यह कल्चर है, उनकी छ्ह में है। कांग्रेसी समाजसेवा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए राजनीति करते हैं। पार्टी से पहले स्वयं को महत्व देते हैं। यही होता रहता है। कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गलत होता है, इसीलिए ऐसी स्थिति आती है।22

टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस के असंतोष पर मुखर हुए भाजपा सांसद और विधायक, परिणाम की कर दी भविष्यवाणी

रायपुर। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद कार्यकर्ताओं के असंतोष को देखते हुए भाजपा के नेता मुखर हो गए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तो निकाय चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी कर दी है। वहीं विधायक सुनील सोनी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दर्द बयां किया है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि असंतुष्टि ही कांग्रेस को डुबायेगी, और उनकी असंतुष्टि में ही बीजेपी का कमल फूल खिलेगा। टिकट खरीदी-बिक्री को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ऊपर स्तर तक पैसे पर पैसे से ही बात होती है, फिर ये तो निचले स्तर की बात है।

वहीं टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं की बगावत को लेकर दूसरी ओर विधायक सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस ने अंतिम समय तक कार्यकर्ताओं को रुलाया है। पैसों के नाम पर कार्यकर्ताओं ने खून के आंसू बहाए हैं, और फिर टिकट के लिए चक्कर कटवाए। कांग्रेस नेताओं को शर्म आना चाहिए।

कांग्रेस में टिकट खरीदी-बिक्री को लेकर विधायक ने कहा कि इनके पूर्व विधायक ही बता रहे हैं कि टिकट खरीदा और बेचा जाता है। छोटे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा करेंगे तो जनता दूर होगी ही। आने

दिल्ली में घोषणापत्र नहीं, लॉटरी पेश कर रहे हैं राजनीतिक दल

नीरज कुमार दुबे

इस समय दिल्ली में सेल चल रही है। वैसे अक्सर सेल में 50 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा की छूट दी जाती है लेकिन दिल्ली में चुनावी मौसम में चल रही सेल में 100 प्रतिशत की छूट है। यानि सब कुछ मुफ्त। सब कुछ मुफ्त देने से सरकारी खजाने को कितना नुकसान होगा इसकी परवाह किसी को नहीं है क्योंकि हर पार्टी विधानसभा में अपनी सीटें किसी भी कीमत पर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सब कुछ मुफ्त देने से दिल्ली में महंगाई का आलम क्या होगा यह सोचे बिना राजनीतिक दल गारंटियों पर गारंटियों की घोषणा किये जा रहे हैं। सब कुछ मुफ्त देने से लोगों का सशक्तिकरण होने की बजाय उनके निठल्ले बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं लेकिन फिर भी सब कुछ फ्री देने की होड़ में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से आगे निकली जा रही हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा है उसके बावजूद यहां के लोगों को फ्री में सुविधाएं हासिल करने की आदत लगा दी गयी है। सरकारी खजाने को लूटो और लुटाओ की नीति के चलते दिल्ली का राजस्व नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार के अवसर बढ़े, दिल्ली का बजट घाटा बढ़ा लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इसीलिए यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली की सत्ता पाने को आतुर पार्टियां एक दो नहीं बल्कि अपने आधा आधा दर्जन घोषणापत्र जारी कर रही हैं। पहले चुनावों में किसी राजनीतिक दल का घोषणापत्र उसकी नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं से निजात दिलाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता था लेकिन आज पार्टियों का घोषणापत्र उनकी सत्ता लोलुपता को प्रदर्शित कर रहा है। देखा जाये तो यह घोषणापत्र नहीं बल्कि लॉटरी पेश करने जैसा है। दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की ही बात कर लें तो बिजली और पानी फ्री देने की राजनीति शुरू करने वाली इस पार्टी ने पैकेज के रूप में बिजली और पानी के साथ मौत भी फ्री ही रखी है क्योंकि इस पार्टी के राज में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते हर उम्र के लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो गयी हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जन लोकपाल लाने का वादा किया था लेकिन भ्रष्टाचार के नये रिकॉर्ड बना दिये, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने का ढोल पीटा जबकि असल में एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री देकर दारू क्रांति लाई गयी। आम आदमी पार्टी ने सादगी और शुचिता की बात की थी लेकिन उसके नेता शीश महल में रहे और सुरक्षा का बड़ा अमला तथा अन्य सुख सुविधाओं को भोगते रहे। अब ''केजरीवाल की गारंटी'' शीर्षक से पार्टी का जो घोषणापत्र जारी किया गया है वह भी खजाने को लुटाने का छलावा दिखा कर मतदाताओं के मत लूटने का प्रयास लगता है। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र में 15 गारंटी का जिक्र है, जिसमें केजरीवाल ने अपनी पहली गारंटी के रूप में दिल्ली के निवासियों के लिए रोजगार सृजन के ''ठोस'' कदम का वादा किया है। बहरहाल, देखा जाये तो मुफ्त सुविधाएं केवल अल्पकालिक राहत प्रदान करती हैं। जबकि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल सिखाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही मतदाताओं को इन लाभों की कीमत के बारे में पता होना चाहिए जो अंततः जनता की जेब से ही आती है। यहां तक कि निर्धनतम व्यक्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स दे रहा है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी योजनाएं महिलाओं को स्वतंत्र नागरिक के रूप में पहचान देती हैं, लेकिन वे अक्सर महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में सीमित कर देती हैं। देश की सरकार जब भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है तो नागरिकों को सिर्फ लाभार्थी तक सीमित करना गलत होगा क्योंकि सरकार पर निर्भर रह कर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और बिना हर नागरिक के योगदान के देश विकसित नहीं हो सकता।

कांग्रेस की विभाजनकारी राहों से जुड़े खतरे

ललित गर्ग

कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा से विभाजनकारी रही है। इनका एजेंडा ही रहा है देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बंटवारा करके अराजकता का माहौल बनाना। इसके लिये वह कभी संविधान को खतरे में बताती है तो कभी जातिगत जनगणना की मांग करती है। एक बार फिर डॉ. भीमराव आंबेडकर की जन्मस्थली महू में रैली के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह इस पर जोर दिया कि संविधान पर हमला किया जा रहा है और महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है, उससे उसकी विचारशून्यता एवं राजनीति अपरिपक्वता ही प्रकट नहीं हो रही है,, बल्कि देश को बांटने की मानसिकता भी उजागर हो रही है। यदि कांग्रेस के रणनीतिकार एवं नेता यह समझ रहे हैं कि वे संविधान के संदर्भ में भय का भूत खड़ा करने और भाजपा एवं संघ के नेताओं के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से देश की जनता को गुमराह करने, बरगलाने में समर्थ हो जाएंगे तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। उलटे इस क्रम में कांग्रेस की विश्वसनीयता और अधिक गिर सकती रही है और वह हास्यास्पद स्थिति का शिकार होकर अपनी राजनीतिक जमीन को कमजोर ही कर रही है। ऐसा हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनावों में हुआ है और अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी ऐसे ही होते हुए दिख रहे हैं।

संविधान के खतरे में होने के कांग्रेस के दुष्प्रचार का लाभ भले ही कुछ सीमा तक लोकसभा चुनाव मिला हो, लेकिन हर बार मतदाता ऐसे नारों एवं दुष्प्रचार में गुमराह नहीं होने वाला है। वैसे भी काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस इस बात को भी तूल दे रही है कि महात्मा गांधी के साथ डॉ. आंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। ये ऐसी बातें हैं, जिनका कोई मूल्य-महत्व नहीं। यह सब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। यह असत्य एवं झूठ की राजनीति है। कांग्रेस भले ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की बातें कर रही हो, लेकिन सच यह है कि वह सामाजिक विभाजन की खाई को चैड़ा करते हुए देश को जोड़ने नहीं, बल्कि तोड़ने में जुटी हुई है। अब मतदाता समझदार हो चुका है, वह ऐसे झूठे प्रचार में बार-बार नहीं आने वाला है। कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करते हुए भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाने पर ले रही है, लेकिन कांग्रेस की इन कुचालों का भाजपा एवं आरएसएस करारा जबाव दे रहे हैं।

गत दिवस ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा- बंधुभाव ही असली धर्म है। यही बात डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान-प्रस्तुति के समय अपने भाषण में भी समझाई है। भागवत ने कहा- समाज आपसी सद्भावना के आधार पर काम करता है। इसलिए मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रकृति भी हमें विविधता देती है। वे विविधता को जीवन का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन आपको एक-दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपको एक साथ रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस वर्तमान में ही नहीं, बल्कि अतीत में भी विभाजनकारी नीति को बल देते हुए भारतीय इंसानों को बांटती रही है। गांधीजी ने आजादी के बाद ही यह बात समझ ली थी। इसीलिए गांधीजी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस गांधी के अनुसार तो खत्म नहीं हुई लेकिन देश में विभाजनकारी नीति के कारण जनता द्वारा नकारी जा रही है, खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है।

कांग्रेस भारत की 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की भावना को दबा रही है, सनातन परंपरा को दबा रही है। अनेक वर्षों तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए इतनी बेचैन है कि वो हर दिन नफरत, द्वेष एवं घृणा की राजनीति कर रही है। कांग्रेस सांप्रदायिकता और जातिवाद के विष को दिल्ली चुनाव में भी उडेल रही है। हिंदू समाज को तोड़ना और उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना ही कांग्रेस की राजनीति का आधार है और यही उसको रसातल में ले जा रहा है। कांग्रेस की जातिगत जणगणना की मांग भी उसकी विभाजनकारी नीति को ही दर्शाती है। मोदी सरकार जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। सरकार के सामने समस्या केवल यह नहीं है कि जनगणना शीघ्र कराई जाए बल्कि मूल समस्या यह है कि कांग्रेस की जाति आधारित जनगणना की मांग का सामना कैसे किया जाए। विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस जातिगत जनगणना पर जोर दे रही है, जो केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के इरादे से की जा रही है। जातिगत जनगणना का उद्देश्य समाज को चुनावी लाभ के लिए जातियों में गोलबंद करना और जातिगत आरक्षण को तूल देकर वोटबैंक की राजनीति को धार देना है। इसकी पुष्टि विपक्षी नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी के ऐसे बयानों से होती है कि अमुक-अमुक जाति के लोगों को दबाया जा रहा है। यह और कुछ नहीं, समाज को जानबूझकर बांटने की घातक चेष्टा है।

यह सही है कि भारतीय समाज जातियों में विभाजित रहा है, लेकिन अब जब यह विभाजन लगातार कम होता जा रहा है, तब जाति जनगणना कराकर जाति की राजनीति करने वालों को सामाजिक विभाजन का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह जातीय वैमनस्य को ही हवा देगा और इससे विभाजनकारी प्रवृत्तियों के सिर उठाने का ही खतरा है। जातिगत जनगणना बेहद जटिल होने के साथ विभाजनकारी भी है। यही कारण है कि 2011 में मनमोहन सरकार ने जाति जनगणना कराने के बाद भी उसके आंकड़े सार्वजनिक करना सही नहीं समझा था। क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं, जिनकी एक राज्य में सामाजिक और आर्थिक हैसियत दूसरे राज्य से बिल्कुल भिन्न है। इतना ही नहीं, कहीं उनकी गिनती अनुसूचित जाति में होती है तो कहीं पिछड़ी जाति में। जाति जनगणना के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि पिछड़ेपन का एकमात्र आधार जाति है। एक समय ऐसा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज शहरों में किसी को इससे मतलब नहीं कि कौन किस जाति का है। जाति जनगणना कराने का मतलब होगा देश को फिर से जातीय विभाजन की ओर ले जाना। इससे बचने में ही समझदारी है।

कांग्रेस एवं विपक्षी दलों का मोदी और भाजपा के विरोध के अलावा कोई साझा उद्देश्य नहीं है, उलटे उनमें दलगत हितों और महत्वाकांक्षाओं का तल्ख टकराव है। दो लोकसभा चुनावों में हाशिये पर रहे विपक्षी दल तीसरे चुनाव के लिए एक साथ तो आए, पर मकसद पूरा न होने पर वापस अपनी-अपनी राह चलने को बेताब हैं। लोकसभा चुनाव में भी बंगाल, केरल और पंजाब में मित्र दल आपस में ही जोर आजमाइश कर रहे थे। अब दिल्ली में भी कांग्रेस और आप अलग-अलग ताल ठोंकते दिख रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में नाकामी के बाद उसने शायद अपने पुनरुत्थान के लिये दिल्ली के चुनाव को आधार बना लिया है। इसमें कोई बुराई नहीं, पर यह काम आसान नहीं। दशकों तक देश और प्रदेशों पर एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस की दुर्दशा अचानक नहीं हुई। बेशक उसका ऐतिहासिक चुनावी पराभव 2014 में हुआ, लेकिन अपनी कमजोरियों-गलतियों एवं विभाजनकारी नीतियों से वह बहुत पहले से जर्जर होने लगी थी। कांग्रेस न केवल खुद को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी जर्जर बना दिया है, गठबंधन का स्लोगन था, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, लेकिन देश को दिखाए गए उन सपनों का सच डेढ़ साल में सामने आ गया। तनातनी पहले भी दिखती रही, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बात आर-पार तक पहुंच गई। यह एक पुरानी कहावत है कि देश जैसी सरकार के योग्य होता है, वैसी ही सरकार उसे प्राप्त होती है।' दिल्ली में भी ऐसी ही सरकार बनेगी जो दिल्ली के हितों को प्राथमिकता दे, न कि विभाजन को।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

(ख) दूसरे के धन का लालच न कर (न) तप करने वाले की बहुत कीर्ति होती है। यहाँ जूआ न खेलने और खेती आदि में परिश्रम करने से घनी बन जाना, दूसरे के घन का लालच न करना तथा तपश्चर्या से कीति का पाना आदि जो उपदेश दिये गये हैं, वे यथार्थ में ऐसे ही हैं।

अव्यसनी जिमींदारों का घनी होना और तपस्वियों का यशस्वी होना प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः वेद के ऐसे वचनों को यथार्थ कहा जाता है। पुराण-ग्रन्थों में भी यथार्थ वनों का अत्यधिक समावेश है, यथाः (क) यजते क्रतुभिर्देवान्पितृ श्च श्रद्धयान्वितः। गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपाः पुनरेष्यति।। (श्रीमद्भागवत 3 । 32 । 23)

(ग) सर्वदुःखहं व्याधिनाशकं मोक्षदं तथा। सदाचारेषु संध्यायाः प्राधान्यं मुनिपुंगव ।। (देवीभागवत 11 । 20 । 54)

(घ) यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्। विद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुते।। (पद्म, उत्तर0 237 । 32)

अर्थात् (क) जो पुरुष श्रद्धापूर्वक यज्ञादि के द्वारा देवों और पितरों का पूजन करता है वह सकाम कर्मों के प्रताप से चन्द्रलोक में यथासमय निवास करके पुनः जन्म धारण करता है। (ख) सदाचार में संध्योपासन सर्वमुख्य है, संध्या से समस्त दुःखों और व्याधियों का नाश होता है तथा मोक्षप्राप्ति होती है। (ग) जिस पुरुष के हाथ पांव आदि इन्द्रियें और मन वशीभूत हो, तथा जो विद्या-तप-कीर्ति-सम्पन्न हो वह तीर्थस्नान के पूर्ण फल का भागी है।

क्रमशः ...

गंगा-सरस्वती-लक्ष्मी का एक-दूजे को शाप...

आशुतोष गर्ग

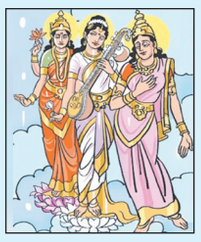

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा, ये तीनों श्रीहरि की भार्या हैं। एक बार सरस्वती को संदेह हो गया कि श्रीहरि गंगा से अधिक प्रेम करते हैं, तो पहले उन्होंने श्रीहरि को कड़े शब्द कहे और फिर गंगा के साथ कठोर बर्ताव करने लगीं। यह देखकर लक्ष्मी ने उनको रोक दिया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को शाप दे दिया, 'तुम वृक्षरूपा और नदीरूपा हो जाओगी।' शाप सुनकर भी लक्ष्मी के मन में सरस्वती के लिए क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ।

परंतु गंगा से यह देखा नहीं गया। उन्होंने पलटकर सरस्वती को शाप दे दिया, 'तुम भी नदीरूपा होकर मर्त्यलोक में चली जाओ, जहां पापी लोग निवास करते हैं।' गंगा का शाप सुनकर सरस्वती को गंगा पर क्रोध आ गया और उन्होंने गंगा को भी शाप दे दिया,?' तुम्हें भी धरातल पर जाकर पापियों के पाप को अंगीकार करना पड़ेगा।' इसी बीच श्रीहरि वहां आ गए। वह लक्ष्मी से बोले, 'शुभे! तुम राजा धर्मध्वज के घर पधारो। परंतु किसी की योनि से उत्पन्न न होकर तुम स्वयं भूमंडल पर प्रकट होना। वहीं तुम वृक्षरूप में निवास करोगी। फिर 'शंखचूड' नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम्हें उसकी पत्नी बनना है। भारतवर्ष में त्रिलोकपावनी 'तुलसी' के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। लेकिन अभी तुम्हें शाप के कारण भारत में 'पद्मावती' नदी बनकर उतरना है।'

इसके बाद श्रीहरि ने गंगा से कहा, 'तुम्हें सरस्वती के शापवश विश्वपावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना है। भगीरथ की तपस्या से तुम्हें वहां जाना पड़ेगा और लोग तुम्हें भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा अंश है। तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना।' फिर श्रीहरि बोले, 'सरस्वती, अपने पूर्ण अंश से ब्रह्मलोक जाकर उनकी कामिनी बनेंगी, गंगा अपने पूर्ण अंश से शिवलोक जाएंगी और लक्ष्मी अपने पूर्ण अंश से मेरे पास रहेंगी।' यह कहकर भगवान श्रीहरि चुप हो गए। इसके बाद गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती, तीनों देवियां एक-दूसरे का आलिंगन करके रोने लगीं। फिर उन्होंने श्रीहरि से अपने-अपने शाप को दूर करने का उपाय और प्रायश्चित के विषय में पूछा।

श्रीहरि भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। तीनों देवियों की प्रार्थना सुनकर विष्णु बोले, सरस्वती, कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाएं, आधे अंश से ब्रह्मा के भवन पर पधारें तथा पूर्ण अंश से मेरे पास रहें। ऐसे ही गंगा भगीरथ के प्रयास से अपने कलांश से भारतवर्ष में जाएं और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास रहें। वहां इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। लक्ष्मी, अपनी कला के अंश से भारतवर्ष में जाएं तथा 'पद्मावती' नदी और 'तुलसी' वृक्ष के रूप में विराजमान हों। कलि के पांच हजार वर्ष पूर्ण हो जाने पर तुम तीनों देवियों का उद्धार हो जाएगा और तुम मेरे भवन पर लौट आओगी। अब मैं तुम्हारी शुद्धि का उपाय बताता हूं। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत-से संत तुम्हारे जल में स्नान करने के लिए आएंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी।' ऐसे बहुत-से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। उनके दर्शन और स्पर्श से आपको इन शापों से मुक्ति मिल जाएगी।' श्रीहरि के वचन सुनकर तीनों देवियां प्रसन्न हुईं और अपने-अपने शाप को भोगने के लिए निकल पड़ीं।

सऊदी समेत इस्लामिक देशों की मदद से तैयार हुआ यूसीसी

अभिनय आकाश

इस वक्त उत्तराखंड पूर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। 27 जनवरी की तारीख को उत्तराखंड ने एक नया ही इतिहास रच दिया। यहां मजहब की दीवारें टूटनी दिखीं। हर नागरिक एक समान कानून में बंधने वाला है। ढाई साल के मंथन और तमाम विवादों के बाद आखिरकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी की यूसीसी लागू हो गया है। सभी पर्सनल लॉ की बजाए अब सभी लोगों को एक कानून का पालन करना होगा। शादी से लेकर तलाक और संपत्ति के अधिकार सभी कुछ मजहबी नहीं बल्कि एक कानून में बंध गया है। मसला मजहब से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको लेकर सवाल और जवाब भी लगातार जारी है। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में लागू हुए यूसीसी में खूबियां क्या हैं और इसका विरोध करने वालों को क्यों ऐतराज हो रहा है? क्यों बार बार कहा जाता है कि यूनिफार्म सिविल कोड इस्लाम के खिलाफ है?

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मैनुअल को मंजूरी दी। इसके बाद इसे लागू करने का रास्ता साफ हुआ। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से ये एक था। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। यह कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए गए वादे को पूरा लिया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है। सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि हम नए कानून यूसीसी को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

समान नागरिक संहिता कानून का मतलब है कि एक ऐसा कानून जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने भरण पोषण जैसे मुद्दों पर सभी धर्म से जुड़े

लोगों पर समान रूप से लागू होगा। भारत में अभी एक समान आपराधिक कानून हैं। लेकिन नागरिक कानून यानी सिविल लॉ अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग हैं। इसमें हलाला, इद्दत, तलाक जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा है। हालांकि आदिवासी समदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समुदाय के लिए शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा समेत कई चीजों में बदलाव आ जाएगा। अब अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानून लागू होगा। लिहाजा अब मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं होगी। वहीं निकाह, हलाला, इद्दत भी गैर कानूनी हो जाएगा।

यूसीसी के लिए उत्तराखंड सरकार के कब क्या कदम उठाए

2022 के चुनाव से एक दिन पहले मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी की घोषणा की

सरकार बनाने के बाद मार्च 2022 की पहली कैबिनेट में समिति गठन को मंजूरी मिली

समिति ने ढाई लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए।

6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ, 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ

11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी, क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को सौंपी।

20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली।

उत्तराखंड में अधिनियम संपूर्ण राज्य पर लागू होगा। ये अधिनियम उत्तराखंड से बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है। अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित अधिकार प्राप्त व्यक्तियों और समुदायों को यूसीसी के मापदंडों से छूट दी गई है।

सीएम द्वारा लॉन्च किया गया ऑनलाइन पोर्टल अगले सप्ताह से उत्तराखंड के नागरिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। https://ucc.uk.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह निवासियों को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और उनकी समाप्ति को पंजीकृत करने की अनुमति देगा। पूरी प्रक्रिया घर से मोबाइल फोन का उपयोग करके पूरी की जा सकती है, आवेदक ईमेल या एसएमएस के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होगा।

यूसीसी के तहत विवाह

यूसीसी पुरुषों और महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु को क्रमशः 21 और 18 वर्ष निर्धारित करता है।

यह सभी समुदायों में बहुविवाह और हलाला दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। हलाला एक विवादास्पद इस्लामी विवाह प्रथा है जहां एक तलाकशुदा महिला दूसरे पुरुष से शादी करती है, फिर अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने के लिए उसे तलाक देती है।

जबकि विवाह की रस्में धार्मिक रीति-रिवाजों या कानूनी प्रावधानों के तहत की जा सकती हैं, 60 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है।

लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

26 मार्च, 2010 से पहले या उत्तराखंड के बाहर हुए विवाहों को अधिनियम लागू होने के 180 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जा सकता है। यह कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

कोई भी सैनिक, किसी अभियान/वास्तविक युद्ध में शामिल वायु सेना कर्मी, या समुद्र में नाविक, विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत कर सकता है, जिसके लिए नियमों को लचीला रखा गया है। यूसीसी वसीयत उत्तराधिकार के तहत वसीयत के निर्माण, रद्दीकरण और संशोधन के साथ-साथ पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल्स के रूप में जाना जाता है, के लिए एक सरलीकृत ढांचा तैयार करता है।

यूसीसी के तहत तलाक

यूसीसी में, पति और पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार समान हैं। इसका मतलब यह है कि अब पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है और पत्नी भी इसी आधार पर तलाक की मांग कर सकती है।

मुस्लिम देशों की क्या है भूमिका

यूसीसी लागू करने के लिए सरकार ने व्यापक विचार विमर्श किया। इस प्रक्रिया में 43 हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की गई। कुल 72 गहन बैठकें हुई। जिसमें जनता से 39 लाख एसएमएस, 28 लाख व्हाट्सएप संदेश और 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। डाक, ईमेल के माध्यम से भी हजारों सुझाव सरकार तक पहुंचे। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों के अध्ययन कर समान नागरिकता संहिता की अवधारण को बेहतर रूप दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये कदम उत्तराखंड को नई पहचान देगा।

कोर्ट में चुनौती देंगी कांग्रेस?

कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर कहा कि जरूरत पड़ी तो इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। खुर्शीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसे होने दें। उन्हें इसे लागू करने दें। उसके बाद हम देखेंगे। मेरा भी उत्तराखंड में घर है। क्या ये मुझ पर भी लागू होगा? इसमें यह भी कहा गया है कि यह उन लोगों पर लागू होगा जो उत्तराखंड के निवासी हैं, चाहे वे कहीं भी रहते हों। तो, यूसीसी उनका कितना पालन करेगी? उन्होंने क्या किया है और किस सोच के साथ ऐसा किया है, हमें समझ में नहीं आता।

आज का इतिहास

1886 कार्ल बेंज ने गैसोलीन ऊर्जा से चालित पहली सफल कार का पेटेंट कराया।

1891 रानी लिलियुओलानी, अंतिम सम्राट और एकमात्र महिला जो हवाई राज्य में शासन करती है।

1916 'प्रथम विश्व युद्ध' में जर्मनी ने फ्रांस पर पहली बार हमला किया।

1921 मलिक फ़ैसल प्रथम को ब्रिटेन द्वारा तैयार की गयी भूमिका के आधार पर इराक़ का नरेश चुना गया।

1943 द्वितीय विश्व युद्ध-रेनाएल द्वीप की लड़ाई, संयुक्त राज्य नौसेना और इंपीरियलजॉपी नौसेना के बीच गुआडलकैनाल अभियान के दौरान अंतिम राजसी सगाई हुई।

1944 द्वितीय विश्व युद्ध-कम से कम 38 लोग मारे गए थे और लगभग एक दर्जन घायल हो गए थे जब सोवियत पार्टिसन इकाइयों द्वारा कोनूची (वर्तमान कन्नुकई, लिथुआनिया) के पोलिश गांव पर हमला किया गया था।

1953 संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई।

1963 फ्रांस के वीटो के कारण यूरोपीय साझा बाजार (ईईसी) में ब्रिटेन को प्रवेश नहीं मिल सका।

1964 अमेरिकी गुप्त रूप से विकसित जेट फाइटर ए -11 का अंत लिंडन बैनेस जॉनसन ने किया।

1967 हिप्पीरा के परम उच्च नामक मंत्र-रॉक नृत्य, सैन फ्रांसिस्को में हुआ, जिसमें स्वामी भक्तिवेदांत, जानिसजोपलिन, आभारी मृत, और एलन गिन्सबर्ग शामिल थे।

1968 सिविल डिसऑर्डर (कर्नर कॉम) पर नस्लवाद के खिलाफ रिपोर्ट और राष्ट्रीय सलाहकार आयोग द्वारा अश्वेतों को सहायता देने की मांग की गई।

1984 कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे इलियट ट्रूडो ने घोषणा की कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं।

1988 टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू पर 107 रन मार्क ग्रेट बैच ने बनाए थे, जब वह इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे।

1991 खाड़ी युद्ध-युद्ध का पहला प्रमुख आधार, खाफीजी की लड़ाई, साथ ही साथ इसका सबसे घातक युद्ध शुरू हुआ।

1992 LPGA महिला केम्पर गोल्फ ओपन चैंपियनशिप डॉन कोए ने जीती।

1996 क्रिकेट विश्व कप में केन्या ने वेस्टइंडीज को 93 रन पर सभी खिलाड़ियों को हराकर बाहर कर दिया।

2000 मोजाम्बिक में बाढ़ में लगभग 700 लोग मारे गए।

2002 अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में ईरान, ईराक़, उत्तरी कोरिया को दुनिया में दुष्टता की धुरी क़रार दिया।

आप लगाएगी जीत की हैट्रिक या किसी और को चुनेगा बवाना

संध्या

दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान हो चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इस कड़ी में हम आपको दिल्ली की सभी सीटों का हाल बता रहे हैं। आज बात बवाना विधानसभा सीट की करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास में बवाना में कब कौन जीता? पिछले चुनाव में कैसे नतीजे रहे थे? इस बार कैसा मुकाबला है? आइये जानते हैं

दिल्ली को विधानसभा कैसे मिली, इसकी कहानी 1952 से शुरू हुई। 1952 पार्ट-सी राज्य के रूप में दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। 1956 में उस विधानसभा को भंग कर दिया गया। 1966 में दिल्ली को एक महानगर परिषद दी गई। दिल्ली राज्य विधानसभा 17 मार्च 1952 को पार्ट-सी राज्य सरकार अधिनियम, 1951 के तहत अस्तित्व में आई। 1952 की विधानसभा में 48 सदस्य थे। मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान था, जिसके संबंध में राज्य विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी।

राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) की सिफारिशों के बाद दिल्ली 1 नवंबर 1956 से भाग-सी राज्य नहीं रही। दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया गया और दिल्ली राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दिल्ली में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन की मांग उठने लगी। इसके बाद दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के तहत महानगर परिषद बनाई गई। यह एक सदनीय लोकतांत्रिक निकाय था जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य और 5 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे।

इसके बाद भी विधानसभा की मांग उठती रही। 24 दिसंबर 1987 को भारत सरकार ने सरकारिया समिति (जिसे बाद में बालकृष्णन समिति कहा गया) नियुक्त की। समिति ने 14 दिसंबर 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सिफारिश की कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए, लेकिन आम आदमी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अच्छी शक्तियों के साथ एक विधानसभा दी जानी चाहिए। बालाकृष्णन समिति की सिफारिश के अनुसार, संसद ने संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 पारित किया, जिसने संविधान में नए अनुच्छेद 239 और 239क्क डाले, जो अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मुद्दों पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। 1992 में परिसीमन के बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव बाद दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा और विधायक मिला।

कैसा रहा बवाना में चुनावों का इतिहास?

बवाना सीट पर पहला चुनाव 1972 में हुआ था। उस समय यहां से निर्दलीय उम्मीदवार टेक चंद ने जीत दर्ज की थी। निर्दलीय उम्मीदवार टेक चंद ने कांग्रेस के राम सिंह को 4,958 वोट से हराया था। इसके बाद बवाना सीट पर साल 1977 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में जनता

पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला हुआ। नतीजा जनता पार्टी के टिकट पर उतरे रोहतास के पक्ष में रहा। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार करतार सिंह को 6,543 मत से शिकस्त दी।

इसके बाद 1983 में भी इस सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें लोकदल के रोहताश सिंह को जीत मिली थी। रोहताश सिंह ने कांग्रेस के करण सिंह को 5,432 वोटों से हराया था।

दिल्ली के विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1993 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में बवाना सीट पर भारतीय जनता पार्टी के चांद राम ने सफलता हासिल की।

1998 में हुए चुनावों में कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार को जीत मिली। इस चुनावों में दूसरे नंबर पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश रंग रहे। कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार को 25,698 वोटों से हरा दिया था। 1998 इस चुनाव में भाजपा ने बवाना समेत तीन सीटें अपने इंडियन नेशनल लोकदल के लिए छोड़ी थीं। बवाना सीट पर इनेलो उम्मीदवार हेम चंद्र तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें कुल 8588 वोट मिले। हेम चंद्र अपनी जमानत भी नहीं बचा सके।

इस चुनाव में बवाना के नतीजे में कुछ नहीं बदला। कांग्रेस के मौजूदा विधायक सुरेंद्र कुमार ने एक और सफलता के साथ यहां लगातार दूसरी जीत दर्ज की। सुरेंद्र कुमार ने भाजपा उम्मीदवार राजकुमार को 14,522 मत से शिकस्त दी।

परिसीमन के बाद बवाना विधानसभा सीट पर हुए चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला हुआ। कांग्रेस से मौजूदा विधायक सुरेंद्र कुमार और भाजपा ने पूर्व विधायक चांद राम को टिकट दिया। हालांकि, चुनावी नतीजा तीसरी बार भी सुरेंद्र कुमार के पक्ष में रहा। कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार ने भाजपा के चांद राम को 17,142 वोट से हराया।

दिल्ली की राजनीति के लिए साल 2013 एक अहम कड़ी साबित हुआ। इस चुनाव में मुकाबले में कांग्रेस-भाजपा के अलावा इस बार भ्रष्टाचार आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी थी। बवाना विधानसभा सीट पर मुकाबला पिछले चुनावों से अलग रहा। चुनाव नतीजे आए तो भाजपा को जीत मिली लेकिन उसे चुनौती नई आम आदमी पार्टी से मिली। 2013 के विधानसभा चुनावों के नतीजों में भाजपा के गुगन सिंह ने आप के मनोज को 25639 वोटों से हराया था। आप को मनोज को 42768 वोट मिले थे। वहीं, लगातार तीन बार बवाना से जीते सुरेंद्र कुमार इस बार तीसरे स्थान पर खिसक गए। सुरेंद्र कुमार को 42,054 वोट से संतोष करना पड़ा।

2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाने पड़े। 2014 में मात्र 49 दिन सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 2014 में जब लोकपाल विधेयक पारित नहीं हो पाया तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2015 में फिर से चुनाव कराए गए और केजरीवाल ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।

इस चुनाव में बवाना सीट पर आप और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला हुआ। आप ने 50,557 वोट के भारी अंतर से चुनाव जीतकर यहां अपना खाता खोला। आप के टिकट पर चुनाव लड़े वेद प्रकाश को यहां से जीत मिली। आप उम्मीदवार वेद प्रकाश को 1,08,928 वोट मिले, जबकि भाजपा गुगन सिंह को केवल 58,371 वोट मिले।

2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फिर जबरदस्त जनादेश हासिल किया। आप को 70 में से कुल 62 सीटों पर जीत मिली। बवाना के नतीजों की बात करें तो यहां से आप के जय भगवान ने जीत दर्ज की। लेकिन ये जीत पिछली बार जितनी बड़ी नहीं थी। आप नेता जय भगवान ने भाजपा के रविंद्र कुमार को 11,526 वोट से हराया था। आप को 95,715 वोट जबकि दूसरे नंबर पर रही भाजपा को 84,189 वोट मिले।

अबकी बार कैसे हैं समीकरण?

2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बवाना सीट से मौजूदा विधायक जय भगवान को टिकट दिया है। वहीं, भाजपा ने यहां से रवीन्द्र कुमार (इंद्रराज) को उतारा है। कांग्रेस ने बवाना सीट से तीन बार विधायक रह चुके सुरेंदर कुमार को फिर से टिकट दिया है।

ट्रंप के आते ही कैसे बढ़ने लगी भारत की मुश्किलें

अभिनय आकाश

20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों का जिक्र किया था। सख्त लहजे में उन्होंने बोला था कि अमेरिका की धरती पर अवैध तरीके से जो प्रवासी रह रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी वो इस पर टिप्पणियां करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अवैध प्रवासियों पर सख्त टिप्पणियां की हैं। लेकिन अब वो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं तो दावा किया जा रहा है कि भारत के 18 से 20 हजार ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। भारत उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप सरकार से बात कर सकता है। दरअसल, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ट्रंप के नए प्रशासन को खुश करने के लिए 20 हजार भारतीयों को वापस डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में प्रवासियों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अनुमानित 20 हजार अप्रवासी इस वक्त अमेरिका में है। इनमें से करीब 2 हजार के लगभग वहां की डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। यूएस कस्टम एंड इमीग्रेशन ने 2 हजार भारतीयों को हटाने का फाइनल ऑर्डर दे दिया है। बाकी के 18 हजार को लेकर भी चर्चा चल रही है। ट्रम्प ने शपथ लेने के बाद अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने के अलावा जन्मजात नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) को खत्म करने को लेकर भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वह आदेश होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति जारी करते हैं। उनका यह आदेश कानून बन जाता है जिसे कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस इन्हें पलट नहीं सकती। हालांकि इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बात चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम इस मुद्दे को लेकर बेहद ही गंभीर हैं और भारत सरकार को इसे हल करना होगा। ऐसे में 18 से 20 हजार भारतीयों को वापस भेजा जा सकता है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारत चाहता है कि एच1बी वीजा प्रोग्राम सरलता से चलता रहे। भारत से बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर अमेरिका जाते हैं। एच1बी वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही मिलता रहा है। अमेरिकी जमीन पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को अपने आप ही नारिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता-पिता का इमिग्रेशन या फिर नागरिकता का स्टेटस कुछ भी हो। ट्रंप के आदेश के लागू होने के नाद अमेरिका में पैदा हुए सच्चे को नागरिकता उसी हालत में मिलेगी, जन उसके माता- पिता में से कोई एक अमेरिकी नागरिक हो, ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर अमेरिकी सेना में हो। अमेरिका में फिलहाल 4.8 मिलियन यानी 48 भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं जो अमेरिका की कुल आबादी का 1.47% है। जबकि 34% लोग अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। इनमें से ज्यादातर इस नए बदलाव से प्रभावित होंगे। बड़ी तादाद में भारतीय मूल के वे लोग भी है, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकता जन्म के वक्त ही हासिल की है। अगर यह नीति लागू होती है तो एच-1बी जैसे अस्थायी वर्क वीजा के तहत काम कर रहे और ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के बच्चों को जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। अमेरिका काम करने एच-1बी वीजा के तहत गए के भारतीयों के लिए उनके तथ्यों को मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता उनकी भी नागरिकता को सुनिश्चित करने में मदद करते है लेकिन अब नई नीति के बाद इन बच्चों की नागरिकता पर ही संकट है। भारतीय स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने वाला दूसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुदाय है।

युद्ध की वजह से 60 वर्ष पीछे चला गया गाजा

आलेक्स मैथ्यूज

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के प्रमुख आशिम श्टाइनर का कहना है कि इस्राएल और हमास के बीच 15 महीने के युद्ध के दौरान, गाजा में 60 सालों से जो विकास हुआ था वह सब खत्म हो गया है। अब वहां 60 से अधिक वर्षों के विकास की भरपाई करने का काम करना होगा। 19 जनवरी को युद्धविराम की शुरुआत के बाद, अब पूरा ध्यान गाजा में लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लाने और वहां पुनर्निर्माण में मदद करने पर केंद्रित हो गया है। अब इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि गाजा में लोगों की जिंदगी फिर से किस तरह पहले वाली स्थिति में आए। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, इस्राएली हवाई हमलों और जमीनी घुसपैठ की वजह से दो-तिहाई से ज्यादा बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है और गाजा पट्टी में लगभग 4.2 करोड़ टन मलबा बिखरा हुआ है।

हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, युद्ध के कारण गाजा में 46,000 लोगों की मौत हुई है। शवों की पहचान का काम तेज होने के साथ, यह संख्या और भी बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र का यह भी कहना है कि वहां समाज के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में दशकों लग सकते हैं और इसकी लागत 80 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। संघर्षविराम के बाद गाजा में अपने उजड़े घरों की ओर लौटते फलीस्तीनी लोगसंघर्षविराम के बाद गाजा में अपने उजड़े घरों की ओर लौटते फलीस्तीनी लोग श्टाइनर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के प्रमुख हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो फलीस्तीनियों की मदद कर रही है, खासकर हमास के नियंत्रण वाले फलीस्तीनी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में।

स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर एक साक्षात्कार में उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, हमारा अनुमान है कि 60 से अधिक वर्षों के दौरान हुआ विकास कार्य पूरी तरह खत्म हो चुका है। 67 फीसदी बुनियादी ढांचा या तो क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा, हम ऐसी स्थिति से निपट रहे हैं जहां अधिकांश गाजावासी या तो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त इमारत में लौटेंगे जिनमें रहना संभव नहीं होगा या फिर वे सिर्फ मलबे के ढेर के पास रहेंगे। यह मलबा खतरनाक है। वहां ऐसे शव हो सकते हैं

जिन्हें अभी तक निकाला नहीं गया है। साथ ही, वहां बिना फटे हुए विस्फोटक और लैंडमाइन भी हो सकते हैं। यह बेहद जहरीला वातावरण है।

संघर्षविराम के बाद गधा गाड़ी पर अपना सामान रख कर घर की ओर लौटता एक फलीस्तीनी परिवारसंघर्षविराम के बाद गधा गाड़ी पर अपना सामान रख कर घर की ओर लौटता एक फलीस्तीनी परिवार श्टाइनर का कहना है कि गाजा में जल्द से जल्द आवश्यक खाद्य सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने की जरूरत है। साथ ही, शुरुआती प्रयासों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे कि सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जल्दी ठीक करना होगा। इसके बाद, मलबे को हटाने और घरों, स्कूलों और अस्पतालों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। श्टाइनर के मुताबिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के साथ-साथ लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा, अपने रिश्तेदारों को खोजने में उनकी मदद करनी होगी।

उन्होंने कहा, अगर आप देखें कि लोगों ने किस तरह का दर्द झेला है, तो पता चलेगा कि सिर्फ बुनियादी ढांचे का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि लोगों ने अपने हजारों रिश्तेदारों को खो दिया है। वह आगे कहते हैं, यह गाजा के लोगों के लिए बहुत बड़ा आघात है। इससे उबरने में उन्हें कई वर्ष लग जाएंगे। शायद बहुत से बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। उन्हें अजनबी लोगों ने अपने तंबुओं में शरण दी है और उनकी देखभाल कर रहे हैं। मिस्र और गाजा की सीमा पर राफा में सीमा पार करने के इंतजार में खड़े ट्रक मिस्र और गाजा की सीमा पर राफा में सीमा पार करने के इंतजार में खड़े ट्रक

किसी भी पुनर्निर्माण की शुरुआत के लिए, इस्राएल और हमास के बीच युद्ध विराम जारी रहना चाहिए। श्टाइनर ने बताया, अभी भी बहुत चिंता है। क्या युद्धविराम जारी रहेगा? क्या दूसरे और तीसरे चरण पर बातचीत आगे बढ़ेगी? दरअसल, युद्ध विराम के दूसरे चरण में लड़ाई का स्थाई अंत, इस्राएल की जेलों में बंद फलीस्तीनी बंदियों के बदले में शेष बंधकों की रिहाई और गाजा से इस्राएली सैनिकों की वापसी शामिल है। तीसरे चरण में गाजा के पुनर्निर्माण की योजना है। श्टाइनर ने कहा कि अगर युद्ध विराम जारी रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने शुरुआती मानवीय कार्यों के लिए मदद देने का वादा किया है। हालांकि, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और निजी क्षेत्र से लंबे समय तक मदद की जरूरत होगी। श्टाइनर कहते हैं, शुरुआती पुनर्निर्माण और फिर लंबे समय तक चलने वाली इस प्रक्रिया के लिए दसियों अरब डॉलर की जरूरत होगी। इसके लिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़कर मदद करनी होगी। निजी क्षेत्र भी इस पुनर्निर्माण कार्य में निवेश कर सकता है। अगले कुछ वर्षों में इस विशाल शुरुआती पुनर्निर्माण कार्य के लिए संसाधन जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।

श्टाइनर का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को गाजा के पुनर्निर्माण के लिए पैसा देना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। उनका तर्क है कि गाजा में शांति बने रहना अमेरिका और यूरोप के राजनीतिक हित में है। श्टाइनर को उम्मीद है कि मध्य पूर्व के देश भी इस पुनर्निर्माण कार्य में मदद करेंगे। हालांकि, लेबनान और सीरिया अभी अपने देश में ही पुनर्निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं। वह कहते हैं कि यह भी जरूरी है कि इस्राएल बातचीत जारी रखे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि किसी भी संघर्ष में इस्राएल को ईमानदारी से और 'सद्भावना के साथ बातचीत करनी चाहिए।

दरअसल, इस्राएल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर, 2023 को हुई थी। इस दिन हमास ने दक्षिणी इस्राएल में आतंकी हमला किया था। हमास को कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। उस हमले में 1,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था।

सीएम सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस चुप क्यों

योगेंद्र योगी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी की तरह झूठे वादे करते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे लेकिन क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार हटा क्या? अडानी पर भी केजरीवाल कुछ भी नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने जब केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसी समय कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले के संबंध में 300 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 142 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। ईडी के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को जब्त किया। ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ईडी ने लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।

आतंरिक तौर पर देखें तो राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे में इतना साहस भी नहीं हो सका कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाना तो दूर बल्कि कारण बताओ नोटिस तक जारी कर सकें। दरअसल कांग्रेस को अंदाजा है कि यदि सिद्धारमैया से कुछ भी पूछा गया तो विद्रोह की नौबत आ जाएगी। ऐसे में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखना ही सही समझा। कांग्रेस को शायद यह बात समझ में नहीं आई कि उसकी चुप्पी ही उसे अपराधी बना रही है। यही वजह है कि भाजपा ने विगत चुनावों में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस की बखिया उधडने में कोई कसर बाकी नहीं रखी।

दरअसल कमजोर होती कांग्रेस में इतने क्षत्रप पनप गए हैं कि पार्टी चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में भ्रष्टाचार हो या पार्टी विरोधी गतिविधियां, कांग्रेस खिसकते जनाधार के कारण यह जहर पीने को मजबूर हो

गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उदाहरण हैं। सरेआम पार्टी के निर्णयों की उपेक्षा करने के बावजूद कांग्रेस गहलोत के खिलाफ कोई कार्ररवाई नहीं कर सकी। इसी तरह सचिन पायलट भी पार्टी खुल कर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, किन्तु कांग्रेस उनकी तरफ से भी आंखे फेरे रही है। गहलोत और पायलट के अंदरूनी सता संघर्ष का ही नतीजा रहा कि कमजोर कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकी और करारी शिकस्त खाने को मजबूर हुई।

कांग्रेस में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने वाले सिद्धारमैया अकेले नेता नहीं हैं। पार्टी में नीचे से लेकर शीर्ष तक नेताओं के खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं। यहां तक कि पार्टी चलाने वालीं कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जमानत पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कई भाषणों में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के जमानत पर बाहर होने पर चुटकी भी लेते रहे हैं। संसद के सत्र के दौरान जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते, तब पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा था- जमानत पर हैं तो एन्जॉय करिए। इसी तरह कांग्रेस मौके-बेमौके ऐसे मुद्दें पर उपहास का पात्र बनती रही है। भ्रष्टाचार के मामलों को देखें तो दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के बड़े कांग्रेस नेता सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसी एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार करती है। नेशनल हेराल्ड केस-2011 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता फंसे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया।

वर्ष 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड वीआइपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला में सीबीआई और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां अहमद पटेल पर इतालवी चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोपों की जांच कर रही हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी फंसे हैं। राजस्थान में एंबुलेस घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी आरोपी हैं। ये मामला 2010 से लेकर 2013 तक एनआरएचएम के तहत एंबुलेंस खरीदने में हुई धांधली का है। ईडी अब तक 12 करोड़ की संपत्तियां आरोपियों से जब्त कर चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने का मामला चल रहा है। 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीके शिवकुमार के 64 ठिकानों पर जबर्दस्त छापेमारी की थी। टैक्स चोरी की शिकायतों पर यह कार्रवाई हुई थी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के खिलाफ भी केंद्रीय एजेंसियों ने छापेमारी की। सितंबर 2015 में उनकी बेटी की शादी के दिन सीबीआई ने छापेमारी कर खलबली मचा दी थी।

आश्चर्य यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, बल्कि लगाने वाले ने अपनी पार्टी की गिरेबां में झांक कर नहीं देखा। आकंठ तक भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस के मुंह से भ्रष्टाचार शब्द भी अब बेजान हो गया है। कांग्रेस का इतिहास और वर्तमान भ्रष्टाचार के काले कारनामों से रंगा हुआ है। कांग्रेस यदि आज देश में लगातार सिमटती जा रही है तो उसका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार में लिप्त होना है। भाजपा के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अपने दामन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर दोमुंही बातें करती रही है। यह निश्चित है कि जब तक कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर कथनी और करनी के फर्क को नहीं मिटाती तब तक देश के मतदाताओं का पूरा भरोसा नहीं जीत सकती।

आखिर ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना क्यों चाहते हैं?

स्कॉट एल. मॉन्टगोमेरी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर कूटनीतिक विवाद को जन्म दिया है कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का अधिग्रहण किया जाना जरूरी है। इस पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने कहा, ग्रीनलैंड हमारे आधिपत्य में है और यह बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड में ट्रंप की रुचि कोई नई नहीं है। इसको लेकर उन्होंने वर्ष 2019 में भी अपनी इच्छा जाहिर की थी। हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में ट्रंप किस तरह अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहनाते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों और आर्कटिक से जुड़े भू-राजनीतिक संघर्षों के विशेषज्ञ के रूप में मेरा मानना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ग्रीनलैंड के महत्व को चार संदर्भों में देखा जा सकता है। ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहां सोना व प्लैटिनम जैसी कीमती धातुओं के अकूत भंडार हैं, तो जस्ता, लोहा, यूरेनियम, तांबा, निकल व कोबाल्ट सहित नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और प्रेसियोडायमियम जैसे दुर्लभ तत्व भी मौजूद हैं। डेनमार्क व ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक, बर्फ की चादर के निरंतर पीछे हटने पर नए भंडार मिलेंगे। ग्रीनलैंड में मौजूद दुर्लभ तत्व न केवल सौर और पवन ऊर्जा आधारित तकनीकों, बल्कि सैन्य अनुप्रयोगों के लिए भी आवश्यक हैं। करीब एक दशक से ग्रीनलैंड पर चीन भी अपनी नजरें गढ़ाए बैठा है। वर्ष 2015 में ग्रीनलैंड के वित्त और आंतरिक मंत्री विट्स क्यूजौकित्सोक ने खनन, जलविद्युत, बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में संभावित निवेश पर चर्चा करने के लिए चीन का दौरा किया था। एक फर्म, चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दो हवाई अड्डे बनाने के लिए बोली लगाई, एक राजधानी नुउक में, दूसरा इलुलिसैट में। दूसरी चीनी फर्म, जनरल नाइस ग्रुप ने उत्तर-पूर्वी ग्रीनलैंड में एक परित्यक्त डेनिश नौसैनिक अड्डे को खरीदने की पेशकश की है, जबकि चीनी विज्ञान अकादमी ने नुउक के पास एक स्थायी अनुसंधान केंद्र और एक उपग्रह ग्राउंड स्टेशन बनाने की बात की है। वर्ष 1946 से ही अमेरिका की ग्रीनलैंड में रुचि रही है, जब उसने 10 करोड़ डॉलर के सोने की पेशकश की थी। उस वक्त डेनमार्क ने प्रस्ताव नकार दिया था। 1950 के दशक में अमेरिका ने आर्कटिक सर्कल के उत्तर में करीब 1,200 किलोमीटर दूर थुले वायुसेना बेस बनाया। 2023 में इसका नाम बदलकर पिटफिक स्पेस बेस कर दिया गया। अमेरिका की सबसे उत्तरी सैन्य सुविधा पिटफिक ने मिसाइल चेतावनी, रक्षा और अंतरिक्ष निगरानी व उपग्रह कमांड मिशन प्रदान करने के लिए रडार और ट्रैकिंग क्षमताओं को अद्यतन किया है। लेकिन चीन का यह दावा कि इस क्षेत्र में नेविगेशन, मछली पकड़ने, ओवरफ्लाइट और तेल व गैस परियोजनाओं में निवेश करने का उसका अधिकार है, अमेरिका को चिंतित करता है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी समुद्री मार्ग और उत्तर पश्चिमी मार्ग, दो आर्कटिक शिपिंग मार्गों के बीच स्थित है, जिसका महत्व समुद्री बर्फ के सिकुड़ने के साथ बढ़ रहा है। 2050 तक मध्य आर्कटिक महासागर के माध्यम से एक ट्रांसपोलर समुद्री मार्ग खुलने की संभावना है। लेकिन ग्रीनलैंड की करीब साठ हजार की आबादी इसे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है। बीजिंग की इच्छा भी ग्रीनलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र बनने देने में है, जिससे इसकी निर्भरता नाटो और यूरोपीय देशों पर कम हो जाएगी और चीन अपने हित स्वतंत्र सरकार से पूरे करवा सकेगा।

कहीं आप जाने-अनजाने हेलीकॉप्टर पेरेंट तो नहीं बन गए हैं

क्या आप जानते है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है? अगर नहीं तो अब जान लीजिए और खुद को भी परख लीजिए कि कही आप जाने-अनजाने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग तो नहीं बन गए हैं।

हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या है?

हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग यानि कि ऐसे अभिभावक जो बच्चों के ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह मंडराते रहते हैं। बच्चों पर अत्यधिक कंट्रोल रखते हैं, उन पर जरूरत से दा ध्यान देते हैं, उन्हें ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए अत्यधिक पजेसिव होते हैं और अधिकांश समय बच्चों के साथ ही रहते हैं। यहां तक कि ऐसे अभिभावक बच्चों को उनका पर्सनल स्पेस भी देना भूल जाते है। आज के दौर में बच्चों को हर प्रकार से सही मार्गदर्शन देना जरूरी है, लेकिन हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बच्चे के बेहद छोटे-छोटे कामों में भी हस्तक्षेप करते है और उनसे जुड़े छोटे-छोटे निर्णय भी खुद ही लेते हैं जैसे दोस्त चुनना, घूमने जाना, खेलना आदि। आइए, जानते हैं कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से बच्चे को क्या नुकसान हो सकते हैं -

- ऐसे अभिभावक बच्चों के जूते के फीते बांधने से लेकर उनके खाने की प्लेट उठाना, लंच पैक करके देना आदि छोटे-छोटे काम खुद ही कर देते हैं। इससे बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते।
- ऐसे अभिभावक बच्चे को अपनी बात कहने का मौका नहीं देते, क्योंकि दूसरों के सामने वे खुद ही बच्चे का पक्ष रख देते है। इससे आगे जाकर बच्चा किसी के सामने खुद अपनी बात को सही तरीके से रखना नहीं सीख पाता और कई बार चुनौती और असफलता हैंडल नहीं कर पाता।
- ऐसे बच्चे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना नहीं सीख पाते क्योंकि हर बुरी बला से बचाने के लिए मातापिता हर वक्त आपके आस-पास ही मौजूद रहते हैं।
- ऐसे बच्चे अगर मातापिता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते तो उनके डिप्रैशन में जाने की आशंका अधिक रहती है।
- ऐसे बच्चे सफल होने का श्रेय कभी स्वयं नहीं ले पाते क्योंकि सफलता उन्हें मातापिता की बदौलत मिलती है।

परिस्थितियों का करें पूरी हिम्मत से सामना

जीवन में परिस्थितियां कब बदल जाएं, हम कह नहीं सकते। कभी जो हमारे बेहद करीब थे, वो कब हमसे दूर चले जाएं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन मजबूत इंसान वही है, जो हर परिस्थितियों का सामना पूरी हिम्मत से करता हो। हम में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने कभी न कभी अपनों को खोया होगा। लेकिन कुछ लोग इससे उबर जाते हैं, तो कुछ खुद को हमेशा उसी परिस्थिति में पाते हैं। अपनों को खोने का दर्द बहुत गहरा होता है। खासकर उस अपने को, जो हमारे बेहद करीब थे। लेकिन इन परिस्थितियों से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही समय पर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। आखिर कैसे हम इस पूरी परिस्थिति से निकल सकते है? कैसे खुद को मजबूत रख सकते है? आइए जानते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारे अपने कभी-भी हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। यदि आप उन्हें याद करके दु:खी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन्हें भी दुख पहुंचा रहे हैं। कोशिश करें कि खुद को आप मजबूत बनाए रखें। यादों से निकलकर वर्तमान के बारे में सोचिए। जानते हैं यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यही हिम्मत आपको इस दु:ख से निकाल सकती है। आपके साथ मौजूद आपके अपने आपको इस परिस्थिति में देखकर कितने दु:खी होंगे?

खुद को व्यस्त रखें। आपका व्यस्त रहना बेहद आवश्यक है। आप कुछ नया सीखने की कोशिश करें जिससे कि खुद को व्यस्त रख सकें। दूसरों के साथ समय बिताएं, अकेले न रहें। कोशिश करें कि आप अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ समय बिताएं जिससे कि आपको अकेले रहने का समय ही न मिले। रात में सोने से पहले अच्छी किताब पढ़ें। किताबें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं।

अगर आपको पेट्स पालने का शौक है, तो घर में जरूर एक नया मेहमान लेकर आएं। यह आपके मूड को फ्रेश भी रखेगा, साथ ही आप इनके साथ व्यस्त भी रहेंगे।

नेल पॉलिश लगाते वक्त ध्यान रखें यह जरूरी बातें

नेल पॉलिश लगाने से पहले नाखून काटने के साथ ही उसे सही शेप देना भी जरूरी है। साथ ही नाखून को सुखाना भी जरूरी है, क्योंकि गीले नाखून पर नेल पेंट लगाने से कोट अच्छी तरह नहीं चढ़ता है और वह जल्दी छूट जाता है। नेल पॉलिश हाथों की खूबसूरती बढ़ाता है, लेकिन नेल पेंट यदि सही तरीके से न लगाया जाए तो यह हाथों की खूबसूरती बढ़ाने की बजाय बिगाड़ सकता है। नाखूनों की सुंदरता बढ़ाने के लिए नेल पॉलिश को सही तरीके से लगाना और नाखूनों की सही देखभाल भी जरूरी है। ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, नेल पेंट आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसे सही तरीके से अप्लाई करना जरूरी है, तभी यह परफेक्ट दिखता है।

हाथों का रखें ख्याल

यदि आपके हाथ रूखे होंगे तो कितनी भी अच्छी नेल पॉलिश क्यों न लगा लें, उसकी खूबसूरती उभरकर नहीं आएगी। इसलिए समय-समय पर मेनिक्योर कराती रहें, इससे हाथ और नाखून दोनों साफ और सुंदर रहते हैं और नेल पेंट का रंग उभरकर दिखता है।

नाखून को शेप

ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, नेल पॉलिश लगाने से पहले नाखून काटने के साथ ही उसे सही शेप देना भी जरूरी है। साथ ही नाखून को सुखाना भी जरूरी है, क्योंकि गीले नाखून पर नेल पेंट लगाने से कोट अच्छी तरह नहीं चढ़ता है और वह जल्दी छूट जाता है।

बेस कोट

यदि आप चाहती हैं नेल पेंट का रंग सही तरह से चढ़े, तो पहले ट्रांस्पेरेंट बेस कोट लगाना जरूरी है। नेल पेंट को ब्रश से पहले नाखून के बीच से लगाना शुरू करें और फिर पूरे नाखून पर लगाकर अच्छी तरह सुखा लें।

पहला कोट लगाएं

ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब ट्रांस्पेरेंट बेस कोट सूख जाए, तब अपनी पसंद की कोई भी नेलपॉलिश लगाएं। पहला कोट लगाने के बाद जब वह अच्छी तरह सूख जाए, तो आप चाहे तो दूसरा कोट लगा सकती हैं। इसे अच्छी तरह सेट करने के लिए आप बर्फ के पानी में उंगलियां डुबोकर रखें। इससे नेल पॉलिश में चमक आ जाएगी।

किनारों को साफ कर लें

यदि नेल पॉलिश लगाते समय किनारों में फैल गई है, तो उसे रिमूवर से साफ कर लें।

इन बातों का भी रखें ध्यान

- आप नेल पेंट को जल्दी सुखाना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए पंखा चालू करके नेल पॉलिश न लगाएं, वरना नेल पेंट सूख जाएगा।
- यदि पहला कोट ठीक से नहीं लगा है, तो दूसरा कोट अप्लाई करे वह स्मूद दिखने लगेगा।
- नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद कुछ दिनों तक नाखूनों को ऐसे ही रहने दें और नेल क्रीम लगाएं, इससे नाखूनों की चमक बढ़ेगी।
- पैर की उंगलियों में नेल पॉलिश लगाते समय दो उंगलियों के बीच में कॉटन लगा ले, इससे नेल पेंट फैलेगा नहीं।
- नेल पॉलिश लगाने से पहले बोतल को अच्छी तरह शेक कर लें।
- हमेशा अच्छी क्वालिटी की नेल पॉलिश ही इस्तेमाल करें, जो ज्यादा दिनों तक टिकती है और नाखूनों को नुकसान नहीं पहुंचाती।

सिल्क की साड़ी की चमक बनाए रखने के लिए इस तरह से करें वॉश

महिलाएं ट्रेडिशनल लुक के लिए सिल्क की साड़ी पहनना पसंद करती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर आम महिलाएं सिल्क की साड़ी पहनती हैं। सिल्क की साड़ी की एक अलग ही चमक होती हैं। सिल्क साड़ी बहुत महंगी आती है। जिसकी वजह से साड़ी की केयर करना बहुत जरुर होता है। अगर सिल्क की साड़ी की सही से केयर ना की जाए तो साड़ी की चमक खो जाती है। महिलाएं सिल्क साड़ी को घर में वॉश नहीं करती है बल्कि ड्राई क्लीनिंग के लिए देती हैं। लेकिन हर बार साड़ी को ड्राई क्लीनिंग में देना काफी महंगा पड़ता है। आप सिल्क की साड़ी को घर में भी साफ कर सकती हैं। सिल्क की साड़ी को घर में सही तरीके से धोने से ना तो साड़ी की चमक कम होती है और ना ही साड़ी खराब होती हैं। चलिए जातने है सिल्क की साड़ी को वॉश करने का सही तरीका।

हाथ से धोना

सिल्क की साड़ी को घर पर हाथ से धोना चाहिए। सिल्क की साड़ी को धोने के लिए सबसे पहले आप एक बाल्टी में पानी लें। पानी सिल्क साड़ी वाला डिटर्जेंट पाउडर लें। अगर आप के पास डिटर्जेंट नहीं तो आप बेबी शैंपू का यूज कर सकती हैं। इसके बाद साड़ी को पांच मिनट के लिए पानी में भिगोएं। इसके बाद सिंपल पानी डाले। इस पानी में थोड़ा सा व्हाइट विनेगर डाले। विनेगर डालने से साड़ी से अतिरिक्त साबुन हट जाता है। इसके बाद तीसरी बार पानी डालकर फैब्रिक कंडीशनर मिक्स करें। इसके बाद साफ और सूखे कपड़े के ऊपर सिल्क साड़ी को रखकर रोल करें। अब टॉवल को हल्के से दबाकर साड़ी से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल दें। इसके बाद साड़ी को दूसरे सूखें टावल पर रखें और हवा में सूखने दें।

सिल्क की साड़ी का दाग

अगर आपकी सिल्क की साड़ी पर दाग लग गया है तो आप इन बतों का ध्यान दें। दाग लगने के तुरंत बाद उसे साफ कर दें। दाग सूखने के बाद उसके निशान को हटाना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा आप व्हाइट विनेगर और नींबू के रस की मदद से दाग हटा सकते हैं।

इन बातों का रखें ख्याल

सिल्क साड़ी को वॉश करने से पहले उसका रंग का टेस्ट जरुर करें। सिल्क साड़ी का कलर तो नहीं निकल रहा है। सिल्क साड़ी का क्लीनिंग डिटर्जेंट सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि हार्ट और ब्लीच आपकी साड़ी को खराब कर सकती है।

इन चीजों के कारण गंदा नजर आता है घर

हर व्यक्ति हमेशा अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहता है। एक साफ घर न केवल अच्छा दिखता है, बल्कि सकारात्मकता भी लाता है। वहीं दूसरी ओर अगर घर गंदा व अव्यवस्थित नजर आए तो इससे मन भी अशांत होता है और घर में नकारात्मकता भी पैदा होती है। हो सकता है कि आप घर को साफ-सुथरा रखते हो, लेकिन फिर भी वह मैसी व गंदा नजर आता हो। ऐसा घर में मौजूद कुछ चीजों के कारण होता है। हालांकि अगर आप इन्हें सही तरह से रखने पर ध्यान देते हैं तो इससे आपका घर हर समय अधिक व्यवस्थित दिखेगा। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी वजह से आपका घर हमेशा गंदा नजर आता है-

भरी हुई किचन स्लैब

हम सभी जानते हैं कि एक भरी हुई किचन स्लैब हमेशा गंदी नजर आती है। ऐसे में आपको स्लैब को पहले क्रमबद्ध रखना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मसलन, किचन में एक साथ एक ही समय में 2 से 3 कार्य ना करें। जिस क्षण आप एक कार्य पूरा करते हैं, तो पहले उसे साफ करें। उसके बाद ही आप किचन में दूसरा काम फैलाएं।

बदबूदार पोंछे व मॉप्स

भले ही आपने अपने किचन को साफ सुथरा रखा हो, लेकिन अगर वहां पर बदबूदार मॉप और पोंछे हैं तो इससे आपकी किचन व घर गंदा लगता है। ताजा और साफ मोप हमेशा आपके घर को एक अच्छा इफेक्ट देते हैं और इससे आपकी रसोई भी सुव्यवस्थित दिखती है।

भरी हुई डाइनिंग टेबल

हममें से अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अपनी डाइनिंग टेबल को साफ-सुथरा और क्लटर फ्री रखना भी बहुत जरूरी है। अमूमन लोग डाइनिंग टेबल पर कटलरी के अलावा, टिश्यू, नमक, काली मिर्च, सॉस और अचार आदि रखते हैं। लेकिन इससे डाइनिंग टेबल काफी भरी और गंदी नजर आती है। इसलिए, हो सके तो डाइनिंग टेबल को मिनिमल ही रखें, इससे आपका लिविंग रूम व डाइनिंग एरिया उतना ही बेहतर लगेगा।

बिना लिड की लॉन्ड्री बास्केट

अमूमन घर में हम गंदे कपड़ों को रखने के लिए लॉन्ड्री बास्केट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे घर काफी मैसी लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप लॉन्ड्री बास्केट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि उसके साथ ढक्कन जरूर हो। कवर वाला लॉन्ड्री बास्केट देखने में अव्यवस्थित नहीं लगता है। लॉन्ड्री बास्केट की तरह आपको डस्टबिन को भी बिना लिड के नहीं रखना चाहिए। यह देखने में काफी गंदा लगेगा।

भरी हुई बालकनी

अक्सर घरों में लोग बालकनी को स्टोरेज की तरह यूज करते हैं। उस एरिया को ब्यूटीफुल बनाने के लिए प्लांट्स तो लगाते हैं, लेकिन छोटी बालकनी में रखीं कुर्सियां व स्टूल्स आदि उसे भरा-भरा दिखाते हैं। इसलिए अपनी बालकनी को थोड़ा स्पेशियस ही बनाए रखें। अगर आप वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वह बहुत अधिक जगह ना घेरे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

31 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू

नईदिल्ली। संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार, 31 जनवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी 2025 को शुरू होगा और 13 फरवरी को समाप्त होगा। सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च 2025 को शुरू होगा और 4 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अठारहवीं लोकसभा का चौथा सत्र शुक्रवार, 31 जनवरी, 2025 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन, सत्र शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025 को समाप्त होने की संभावना है। यह सीतारमण का आठवां बजट होगा- छह वार्षिक और दो अंतरिम- सबसे अधिक बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा। 2017 के बाद से, केंद्रीय बजट लगातार 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है ताकि अप्रैल में नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले घोषणाओं को प्रभावी किया जा सके।

अखिलेश और केजरीवाल 30 को मिलकर करेंगे रोड शो

नईदिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनावी जंग जारी है। इस चुनावी जंग के बीच ही अब नया मोड़ आ गया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेगी। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) पहले ही दिल्ली में सत्तारूढ़ आप को अपना समर्थन दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 30 जनवरी को रिठाला विधानसभा क्षेत्र में एक साथ रोड शो करेंगे। सपा प्रमुख यादव के साथ पार्टी के कई सांसद भी आप के लिए प्रचार करेंगे। आप ने बताया कि कैराना से सांसद इकरा हसन भी विधानसभा चुनाव में आप उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और आप, दोनों पार्टियां जो कि भारत गठबंधन का हिस्सा हैं।

केजरीवाल और सिसोदिया के लिए प्रचार करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। पार्टी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। एक उच्च पदस्थ सूत्र के अनुसार, आसनसोल से टीएमसी सांसद सिन्हा 1 और 2 फरवरी को कम से कम तीन निर्वाचन क्षेत्रों में आप के लिए प्रचार करेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र, मुख्यमंत्री आतिशी का कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र और मनीष सिसोदिया का जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। टीएमसी का मानना है कि अभिनेता से नेता बने, जो बिहार से हैं, दिल्ली के पूर्वांचली मतदाताओं को एकजुट कर सकते हैं, यह शब्द बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को संदर्भित करता है। शहर में पूर्वांचली एक प्रभावशाली मतदाता हैं। सूत्र ने कहा कि एक या दो और टीएमसी नेता दिल्ली में चुनाव प्रचार में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी ने दिल्ली चुनाव के लिए आप को समर्थन दिया था।

यमुना की पानी को लेकर हरियाणा पर बरसीं आतिशी

नईदिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हरियाणा पर दिल्ली को पानी की आपूर्ति को जानबूझकर दूषित करके जल आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है और शहर में लाखों लोगों के लिए पानी की आपूर्ति बाधित कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया कि आगामी चुनाव प्रभावित न हों। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन को प्रभावित करने के प्रयास में हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के लोगों की जल आपूर्ति को बाधित करने के जानबूझकर किए गए प्रयास को उजागर करने वाले मेरे दिनांक 27 जनवरी 2025 के पत्र की निरंतरता में, मैं कल प्रस्तुत एक नोट संलग्न कर रही हूं। यानी 27 जनवरी 2025 को दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने इस मामले पर दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखा।

यमुना पर छिड़ी रार : केजरीवाल पर मानहानि का केस करेंगे सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने दावा किया था कि हरियाणा सरकार औद्योगिक कचरा डालकर यमुना के पानी को जहरीला बना रही है। इस बीच, भाजपा केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसी) का दौरा भी करेगी। इससे पहले सीएम सैनी ने केजरीवाल को आरोप लगाने के बजाय शासन पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को आरोप लगाने और भागने की आदत है। वह (अरविंद केजरीवाल) अमोनिया के बारे में बात करते हैं। वह पानी की कमी का दावा करते हैं। लेकिन कोई कमी नहीं है। सैनी ने कहा कि वितरण प्रणाली में एक मुद्दा है। वह 10 वर्षों में पानी के वितरण का प्रबंधन नहीं कर सकते, हालांकि उन्होंने इसका वादा किया था, फिर भी लोगों को प्रदूषित पानी मिल रहा है।

मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में बोले प्रधानमंत्री

पूर्वी भारत देश का विकास इंजन : मोदी

भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भुवनेश्वर में 'उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव' का उद्घाटन किया। उन्होंने जनता मैदान में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति की मौजूदगी में व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 'मेक इन ओडिशा' प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें जीवंत औद्योगिक परिवेश विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों को दिखाया गया है। दो दिवसीय इस सम्मेलन में बड़े उद्योगपतियों सहित करीब 7,500 कारोबारी प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।

उद्घाटन समारोह में वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला और जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन उद्योग जगत की हस्तियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में ओडिशा द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।

इस दौरान पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि ये ओडिशा में अब तक की सबसे बड़ी बिजनेस समिट है। पहले की मुकाबले 5-6 गुणा ज्यादा निवेशक इस बिजनेस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। मैं इसके लिए ओडिशा सरकार और ओडिशा के लोगों को बहुत बधाई देता हूं।

उन्होने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के दो बड़े स्तंभ हैं। हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स... देश की तेज प्रगति केवल कच्चा माल के निर्यात से संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे इको सिस्टम को बदल रहे हैं। नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। सरकार के प्रयासों के बीच मेरा आपसे कुछ आग्रह भी है।

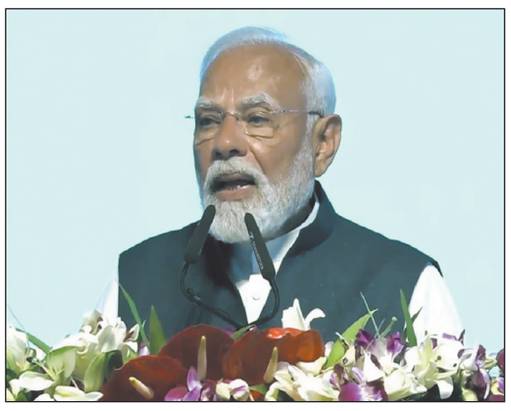

तेजी से बदलती दुनिया में आप ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं। भारत बिखरी हुई सप्लाई चेन और आयात आधारित सप्लाई चेन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। हमें भारत में भी एक सशक्त सप्लाई चेन बनानी है जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। ये सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस से जुड़े एमएसएमई को सहायता करें।

उन्होंने कहा कि मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है कि जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का एक बड़ा योगदान था। पूर्वी भारत में देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब थे, पोर्ट थे, ट्रेड हब थे। ओडिशा की इसमें बड़ी हिस्सेदारी भी थी। ओडिशा साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले ट्रेड का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहां के प्राचीन पोर्ट्स एक प्रकार से भारत के गेट-वे हुआ करते थे।

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत विकास के ऐसे पथ पर चल रहा है, जिसको करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं से बल मिल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि भारत की आकांक्षा हमारी ताकत है। मुझे विश्वास है, ओडिशा बहुत जल्द विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पहुंचने की किसी ने कल्पना भी नहीं की है। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी की पूरी टीम ओडिशा के विकास को तेज गति देने में जुटी है।

उन्होंने कहा, ओडिशा, असाधारण है। ओडिशा, नए भारत के आशावाद और मौलिकता का प्रतीक है। ओडिशा में अवसर भी हैं और यहां के लोगों ने हमेशा सबसे बेहतर करने का जुनून दिखाया है। भारत को वेडिंग डेस्टिनेशन हब बनाने को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का फोकस है- वेड इन इंडिया। आज भारत का मंत्र है- हील इन इंडिया। इसके लिए ओडिशा की प्रकृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता बहुत मददगार है।

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में ओडिशा की बड़ी भूमिका है। ओडिशावासियों ने समृद्ध ओडिशा के निर्माण का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग मिल रहा है।

ओडिशा की विकास की दशा और दिशा ही बदल जाएगी

इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि पिछले 7 महीनों में यह आपका (प्रधानमंत्री मोदी का) ओडिशा का पांचवां दौरा है और आप हमेशा राज्य के लिए सौगात लेकर आते हैं। इस बार आप इतनी बड़ी सौगात लेकर आए हैं कि कुछ ही महीनों में ओडिशा की विकास की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। 7 महीने पहले आपने पूर्वोदय की जो नींव रखी थी, आज उस पर एक मजबूत ढांचे का निर्माण होने जा रहा है।

डुबकी वाले बयान पर भाजपा का खरगे पर पलटवार

कांग्रेस की मानसिकता सनातन के खिलाफ : हिमंत

नई दिल्ली। प्रयागराज में संगम पर भाजपा नेताओं के पवित्र स्नान पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने निशाना साधा है। सीएम सरमा ने कहा कि उनका बयान सनातन के खिलाफ मानसिकता को दर्शाता है। वे आत्मचिंतन करें और अपना रुख तय करें। असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि महाकुंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान सनातन धर्म के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मेरा मानना है कि यह राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रुख है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2001 में सोनिया गांधी ने खुद कुंभ के दौरान पवित्र स्नान किया था। क्या वह यह कहने की हिम्मत करेंगे कि हज पर जाने से भूख और गरीबी जैसी समस्याएं हल नहीं होंगी?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जुड़े सभी हिंदू नेताओं के लिए यह समय है कि वे आत्मचिंतन करें और अपना रुख तय करें। केवल सत्ता और पद के लिए अपने विश्वास, अपने धर्म या इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से समझौता न करें। कोई भी नेता, कोई भी विचारधारा और कोई भी पार्टी आपके धर्म और विश्वास से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सनातन धर्म सहस्राब्दियों से समय की कसौटी पर खरा उतरा है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसके सार को कमतर न आंकें। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलें।

चंद्रशेखर बावनकुले ने भी खरगे को घेरा

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हिंदुओं की आस्था का अपमान करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का सार्वजनिक निषेध किया जाए। कांग्रेस ने हमेशा हिंदू धर्म की अस्मिता, श्रद्धा और भावनाओं का अपमान किया है। इस बार महाकुंभ मेले जैसे पवित्र उत्सव, उसमें श्रद्धा और आस्था के साथ भाग लेने वाले करोड़ों हिंदुओं और गंगा की पवित्रता का मजाक उड़ाकर खरगे ने सारी हदें पार कर दी हैं। गंगा में स्नान करने से क्या इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी? इस तरह का मूर्खतापूर्ण और उतना ही आक्रोशजनक सवाल कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया है। खरगे के इस बयान से पूरे देश में आक्रोश की लहर फैल गई है।

बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा एक विशेष समुदाय का तुष्टिकरण किया है। इस देश के सहिष्णु और बहुसंख्यक हिंदू समाज ने इसे चुपचाप सहन किया और स्वीकार किया। लेकिन ऐसा करते हुए हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक उड़ाने का

अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को किसने दिया? कांग्रेस को हिंदुओं के वोट चाहिए, लेकिन फिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? आखिर हिंदुओं ने ऐसी क्या गलती की है? स्वतंत्र भारत के इतिहास में छह दशक से अधिक समय तक आपको सत्ता में रखा, क्या यही हिंदुओं की गलती है? लोकसभा में भले ही 99 सांसद हों, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान तो कर सकते थे। अगर आप उनका मजाक उड़ाकर अपमान कर रहे हैं, तो यह अधिकार आपको किसने दिया? यह सवाल आज हिंदुस्तान की जनता के मन में उठ रहे हैं।

इस देश की जनता ने लगातार तीन बार कांग्रेस को साफ नकारा, फिर भी कांग्रेस को अक्ल नहीं आई। ऐसे में जनता इस पार्टी को और क्या सजा दे सकती है? निश्चित रूप से देश की समझदार जनता इस पर विचार करेगी। लेकिन आज सत्ता में न रहते हुए भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंभ मेले का मजाक उड़ा रहे हैं। कल अगर गलती से उनकी सत्ता आ गई, तो भविष्य में कुंभ मेले पर प्रतिबंध लगाए बिना ये नहीं रुकेंगे, यह डर आज देश के हिंदू समाज के मन में पैदा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का एक बार फिर से कड़ा विरोध और तीव्र निषेध।

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह सवाल उठाया था

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा नेता तब तक डुबकी लगाते हैं जब तक यह कैमरों में अच्छा दिखे। खरगे ने कहा कि मोदी के झूठे वादों के झांसे में न आएं। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म होती है? क्या इससे आपका पेट भरता है? जब बच्चे भूख से मर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, तब ये लोग हजारों रुपये खर्च कर गंगा में डुबकी लगाने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

रणजी में 13 साल बाद कोहली की होगी वापसी

नई दिल्ली। स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी से पूर्व मंगलवार को यहां दिल्ली टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू की। पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे 36 वर्षीय कोहली 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेलेंगे जिससे इस प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता में उनकी वापसी होगी। उन्होंने अपना पिछला रणजी मुकाबला 2012 में गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेला था। उस समय कोहली भारत क्रिकेट के उभरते हुए सितारे थे, लेकिन अब वह इस खेल के सबसे बड़े मौजूदा दिग्गजों में शामिल है। भारत के इस पूर्व कप्तान के नाम अब 80 अंतरराष्ट्रीय शतक है।

कोहली मंगलवार सुबह ठीक नौ बजे अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे और टीम से मिलने और वार्म अप के बाद उन्होंने टीम के साथियों के साथ करीब 15 मिनट तक फुटबॉल खेला। यह स्टार खिलाड़ी अपने नए साथियों के साथ सहज दिखा। दिल्ली के लगभग सभी खिलाड़ी पहली बार कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर रहे हैं और उन्हें अपने बीच पाकर काफी उत्साहित दिखे। अभ्यास ड्रिल दिल्ली के मुख्य कोच सरनदीप सिंह के मार्गदर्शन में हुई।

डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा ने कहा, हमारे जूनियर खिलाड़ियों के लिए जाहिर तौर पर यह बहुत अच्छा अनुभव होगा क्योंकि उन्हें विराट के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का मौका मिलेगा। आप हमारी टीम पर नजर डालें तो केवल नवदीप सैनी ही भारत के लिए और आईपीएल में विराट के साथ खेले हैं। इस टीम के किसी भी अन्य खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी में विराट के साथ खेलने का अनुभव नहीं है। युवा खिलाड़ी उन्हें देखकर वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैच की व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा, हम जानते हैं कि विराट की उपस्थिति से मैच का महत्व काफी बढ़ जाएगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 535 अंकों की बढ़त के साथ बंद

नईदिल्ली। शेयर मार्केट में आज शानदार रिकवरी का माहौल देखने को मिला। बाजार के प्रमुख इंडेक्स तेजी के साथ कारोबार करते दिखे। दो दिनों की लगातार गिरावट के बाद, बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने मंगलवार को तेज बढ़त के साथ वापसी की। सप्ताह के दूसरे दिन तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसक्स आज 75,659.00 अंक पर खुला था। कारोबार के दौरान यह 76,512.96 अंक के हाईएस्ट और 75,622.88 अंक के नीचले स्तर तक चला गया था। अंत में सेंसेक्स 535.24 अंक या 0.71% की बढ़ोतरी लेकर 76,190.46 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी आज लाल और हरे निशान में झूलने के बाद 128.10 अंक या 0.56% की बढ़ोतरी के साथ 22,957.25 पर बंद हुआ। निफ्टी-50 के 50 में से 28 स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए।

अपना 100वां मिशन लॉन्च करने के लिए इसरो तैयार

श्री हरिकोटा। इसरो के 100वें मिशन जीएसएलवी-एफ 15 रॉकेट के साथ सैटेलाइट एनवीएस-02 को लॉन्च करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज वाले रॉकेट को 29 जनवरी को सुबह 6.23 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा। 27 घंटे का काउंटडाउन पूरा करने के बाद रॉकेट सैटेलाइट को लेकर रवाना होगा। इसके साथ ही यह इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन का पहला मिशन होगा। इसरो ने बताया कि जीएसएलवी-एफ15, एनवीएस-02 सैटेलाइट को भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित करेगा। इसकी 27.30 घंटे की उल्टी गिनती मंगलवार सुबह 02.53 बजे शुरू हुई। इसरो के अनुसार, नेविगेशन विद इंडियन कंस्टीलेशन भारत का स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है।

युवा प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए निवेश किया जा सकता है

तोक्यो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश टोयोटा के लिए सुविधाएं स्थापित करने और तकनीकी नौकरियों में युवाओं के प्रशिक्षण को बढ़ाने में निवेश के लिए एक आदर्श स्थान है। यादव ने राज्य की निवेशक-अनुकूल नीतियों और कुशल कार्यबल उपलब्धता पर जोर दिया और जापान के वाहन विनिर्माता को निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। टोयोटा के वरिष्ठ नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान भारत और मध्य प्रदेश में कंपनी की पहलों तथा परिचालनों पर बात की। राज्य में आगामी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में उन्होंने व्यापार संबंधों की संभावनाओं की समीक्षा करने की मंशा व्यक्त की। यादव जापान की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। यह पिछले वर्ष शुरू किए गए 'मध्य प्रदेश में निवेश' अभियान का हिस्सा है। यह अभियान 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाले 'इन्वेस्ट मध्य प्रदेश' - वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 में सम्पन्न होगा।

डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 83% तक पहुंची

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का डिजिटल भुगतान प्रणाली में योगदान पिछले पांच वर्षों में दोगुना हो गया है। 2019 में जहां यूपीआई का हिस्सा 34 प्रतिशत था, वहीं 2024 में यह बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत, अन्य डिजिटल भुगतान विधियों जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रीयल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस और क्रेडिट और डेबिट कार्ड का हिस्सा 2019 में 66 प्रतिशत से घटकर 2024 के अंत में 17 प्रतिशत रह गया है। 2024 में भारत में कुल 208.5 अरब डिजिटल भुगतान लेन-देन रिकॉर्ड किए गए हैं। भारत की रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली, यूपीआई, की बढ़ती हिस्सेदारी का श्रेय इस डिजिटल भुगतान विधि को अपनाने की बढ़ती गति को दिया जा सकता है।

निवेश के लिए विदेश यात्रा का ऑडिट जरूरी

प्रभु चावला

नेटवर्क अब भारतीय राजनीतिक वर्ग की कुल संपत्ति है। अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का सबसे लोकप्रिय जुनून है। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत नेताओं द्वारा स्विट्जरलैंड के अत्यधिक महंगे स्की शहर दावोस की ओर बढ़ने से होती है, जहां अरबपति पैसों के जरिये देशों की नीति तय करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हमारे राजनेता राजनीतिक पहचान के आधार पर विभाजित हो सकते हैं, परंतु वे विकास के नाम पर अपने राज्यों के लिए विदेशी धन प्राप्त करने के नाम पर एकजुट रहते हैं।

पिछले सप्ताह, पांच केंद्रीय मंत्रियों और तीन मुख्यमंत्रियों को, 100 से अधिक बाबुओं के साथ विश्व आर्थिक मंच जैसे लाभकारी मंच पर वैश्विक दिग्गजों के साथ बातचीत करते हुए, आर्थिक लाभ के लिए पैरवी करते हुए देखा गया था। इन यात्राओं की लागत लगभग 50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति थी। दावोस उनका एकमात्र पड़ाव नहीं है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, वे, उनके मंत्री और भाजपा के मुख्यमंत्री, अन्य दलों के अपने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी समकक्षों के साथ, निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार विश्व की तिजोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, विदेशी पूंजी को लुभाने वाले सबसे सक्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक थे। शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा, जिसने अपने राज्य को पैसा कमाने वाले बाजार के रूप में पेश करके मित्रवत सरकारों को लुभाया न हो। यहां कुछ हालिया भ्रमणों पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में चार बार दावोस जाने वाले देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख हवाई अड्डे पर भारतीय राजदूत द्वारा

स्वागत किया गया, उन्होंने अपने चौथे दिन का जश्न एक्स पर एक शानदार पोस्ट के साथ मनाया- 'यह 22 जनवरी है, एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन।

एक दिन में 6.25 लाख करोड़ रुपये का एमओयू (समझौता ज्ञापन), पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की विकास क्षमता में अटूट विश्वास को दर्शाते हैं।' पिछले वर्ष, उनके पूर्ववर्ती एकनाथ शिंदे ने स्की रिजॉर्ट की अपनी पहली यात्रा को लेकर दावा किया था कि 3,53,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये थे। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य तकनीक और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 2022 में डब्ल्यूइएफ में भाग लिया था। तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के चार महीने बाद से ही निवेश की तलाश में विश्व भ्रमण करने लगे हैं। यूरोप के उनके नवीनतम प्रवास में दावोस भी शामिल था। उन्होंने 40,000 करोड़ रुपये के नये निवेश सौदों पर हस्ताक्षर किये। इससे पहले जनवरी में, रेड्डी की टीम ने 31,500 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करते हुए अपना पहला आधिकारिक अमेरिकी दौरा पूरा किया था। इसके बाद रेड्डी दक्षिण कोरिया चले गये, जहां कंपनियों ने 4,500 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमतौर पर विदेशी दौरे से बचती हैं। हालांकि, मार्च 2024 में उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र में साझेदारी की तलाश में स्पेन का दौरा किया था। मई 2024 में वह भारतीय प्रवासियों और रियल एस्टेट और वित्त क्षेत्रों में संभावित निवेशकों के साथ बातचीत के लिए दुबई गयी थीं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपनी आधिकारिक उड़ान पर अप्रैल 2024 में जापान गये थे। उनकी यह यात्रा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को बढ़ावा देने, ऑटोमोटिव क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट शहरों में जापानी निवेश को आकर्षित करने के लिए थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'गेट एफडीआइ' अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान रक्षा, बुनियादी ढांचे और शिक्षा में संभावित निवेश का पता लगाने के लिए मार्च 2024 में ब्रिटेन का दौरा किया था। उन्होंने व्यवसायियों से मिलने और लॉजिस्टिक्स तथा पर्यटन के क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा करने के लिए मई 2024 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी।

भव्य रैली के साथ मीनल चौबे ने किया मेयर पद पर नामांकन

जगह-जगह चाक-चौराहों पर रायपुर की जनता ने किया स्वागत

भाजपा के कमल निशान वाले झंडे को लेकर कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली

जनता बोली, मीनल चौबे ऐसी नेत्री जो, हमेशा लोगों के सुख-दुःख में रहती हैं शामिल

लगे नारे, मीनल दीदी को जिताना है, शहर में भाजपा का सुशासन लाना है

लगा नारा- बँटोगे तो फिर लुटोगे, मीनल दीदी आएंगी, शहर में भाजपा का सुशासन लाएंगी

रायपुर। नगर निगम रायपुर के मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनल चौबे ने मंगलवार को हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान रायपुर संभाग प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा व मोतीलाल साहू, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, ,नगर निगम रायपुर संगठन प्रभारी संदीप शर्मा,भाजपा नेता अशोक बजाज जिला अध्यक्ष रायपुर शहर रमेश ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, महामंत्री सत्यम दुआ, ओमकार बैस, जिला मंत्री अमित मैशरी सहित भाजपा के पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए।

इसके पूर्व श्रीमती मीनल चौबे ने अपने निवास में भगवान श्रीराम-माता सीता सहित अन्य विग्रहों का पूजन कर नामांकन रैली का शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं के साथ ही रायपुर के सभी वार्ड से स्वस्फूर्त आम जनता भी श्रीमती चौबे के समर्थन में रैली में शामिल हुई। जय श्रीराम के जयघोष के साथ मीनल चौबे अपने वाहन पर सवार हुईं। इसके साथ ही दोपहिया और चार पहिया वाहन के अलावा पैदल ही जब हजारों की संख्या में भव्य रैली निकली तो पूरा शहर भगवा और भाजपामय दिखने लगा। शहर के विभिन्न चौराहों पर रैली के स्वागत करने के लिए जनता भी लालायित दिखी। रैली पर पुष्पवर्षा कर श्रीमती चौबे के प्रति समर्थन जताया। श्रीमती चौबे की रैली को देखने के लिए लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गए थे। अपने घरों की छतों पर खड़े होकर मीनल दीदी और भाजपा जिंदाबाद के

जमकर नारे लगाते दिखे। एक ओर जहां हजारों कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर से जनता के बीच से आवाज गूंज रही थी, खत्म हुआ कांग्रेस का कुशासन, लाएंगे शहर में भाजपा का सुशासान। क्या युवा-बुजुर्ग और महिलाएं सभी में गजब-जोश और उत्साह नजारा दिख रहा था। भव्य रैली को देखकर लोग सहसा ही कह उठ रहे थे कि ये नामांकन नहीं, विजय जुलूस है। क्योंकि कांग्रेस के मेयर ने पूरे शहर को नर्क बना दिया था। रैली के मार्ग पर मौजूद दुकानदार और राहगीरों ने भी हाथ हिलाकर श्रीमती मीनल चौबे का अभिवादन और अपना प्रबल समर्थन देने की इच्छा जाहिर की। इधर श्रीमती मीनल चौबे ने भी अपनी विजय मुद्रा में जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहीं थीं।

पार्षद प्रत्याशी विशाल पाण्डेय, भगतराम हरवंश, मनमोहन मनहरे, नन्दकुमार साहू, अम्बिका साहू, खगपति सोनी, खेमकुमार सेन, आर्ची साहू, गोपेश कुमार साहू, देवदत्त द्विवेदी, मोहन साहू, साधना प्रमोद साहू, महेंद्र खोडियार, सूर्यकांत राठौर, राजेश देवांगन, गज्जू साहू, प्रमिला साहू, सोहन साहू, प्रीतम ठाकुर, अमन ठाकुर, गायत्री सुनील चंद्राकर, मीना ठाकुर, कृष्णा पंचुराम भारती, राधिका साहू, भोलाराम साहू, रामहीन कुर्रे, अवतारसिंह बागल, कृतिका जैन, कैलाश बेहरा, राजेश कुमार गुप्ता, पुष्पा रोहित साहू, प्रभा मनोज विश्वकर्मा, प्रदीप कुमार वर्मा, ज्ञानचंद चौधरी, घनश्याम रक्सेल, श्वेता विश्वकर्मा, दीपक जायसवाल, आनंद अग्रवाल, सुमन अशोक पाण्डेय, आशु चंद्रवंशी, सरिता दुबे, अम्बर अग्रवाल, अजय साहू, मुरली शर्मा, प्रीति परताले, संजना संतोष हियाल, संतोष साहू, महेश ध्रुव, अनामिका सिंह, गायत्री नौरंगे, उत्तरा सिंह, विनय पंकज निर्मलकर, मनोज जांगडे, सुषमा तिलक साहू, विनय प्रताप सिंह ध्रुव, सचिन मेघानी, अमर गिदवानी, श्रीमती स्वप्निल मिश्रा, अंजलि जितेन्द्र गोलछा, रमेश सपहा, रवि सोनकर, बद्री प्रसाद गुप्ता, प्रमोद कुमार साहू, मनोज वर्मा, मंजू राजेंद्र सिंह यादव, श्याम सुंदर अग्रवाल, ममता तिवारी, दुर्गा यादराम साहू, महेंद्र औसर और अर्जुन यादव ने भी रैली में शामिल होकर नामांकन दाखिल किया।

रैली में शामिल भाजपा कार्यकर्ता श्रीमती मीनल चौबे को वोट देकर भारी जीत दिलाने की अपील कर रहे थे तो लोग स्वस्फूर्त श्रीमती मीनल दीदी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। ढोल-नगाड़ों की थाप पर निकली नामांकन रैली जैसे-जैसे नामांकन स्थल की ओर बढ़ती गई, वैसे जगह-जगह वार्ड से भी लोग रैली में शामिल होते गए। कुछ ही समय में भाजपा की नामांकन की रैली ने भव्य रुप ले लिया। इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरूष अपनी भागीदारी निभाई। विहंगम और भव्य रैली को देखकर लोग उत्साह में नारे भी लगाने लगे, यह नामांकन नहीं, विजय जुलूस है।

दीदी श्रीमती मीनल चौबे के प्रति लोगों में अपार प्यार-स्नेह दिखा। उनकी रैली के पहुंचे ही उनका स्वागत किया। पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया तो श्रीमती मीनल चौबे ने भी लोगों पर पुष्प वर्षा कर लोगों का अभिवादन किया। जगह-जगह महिलाओं ने उनकी आरती उतारकर विजयश्री का आशीर्वाद दिया। उन्हें जीत की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि दीदी हमलोग अब किसी भ्रष्टाचारी को नहीं जीतने देंगे, आपकी सेवा के लिए भाजपा ने आपको टिकट देकर पहले ही जीत की पटकथा लिख दी है।

इस रैली के दौरान लोगों ने अपनी भावनाएं भी व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि पांच साल तक पूरे शहर को नर्क बनाने वाले कांग्रेसी मेयर और उसके पार्षदों को इस बार रायपुर की जनता हार का स्वाद चखाएगी। कांग्रेस के जितने भी मेयर हुए, उन लोगों ने विकास के नाम पर सिर्फ लूट मचाई। लोगों को मूलभूत सुविधाओं के नाम पर ठगने का काम किया। न कभी नाली की सफाई हुई और न ही शहर के गार्डेनों का रख-रखाव हुआ।

महाकुंभ को लेकर विवादित टिप्पणी,खड़गे के खिलाफ भाजपा ने दर्ज कराई शिकायत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने महाकुम्भ के आयोजन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा महू में दिए गए बयान को घोर सनातन विरोधी और घृणित सोच का परिचायक बताते हुए खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय वास्तव, जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक जेपी चंद्रवंशी और सह संयोजक बृजेश पांडे ने मंगलवार शाम को सिविल लाइन थाने में इस आशय का आवेदन सौंपा है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री वास्तव, जिलाध्यक्ष ठाकुर, प्रदेश मीडिया चिमनानी, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक चंद्रवंशी और सह संयोजक पांडे ने सिविल लाइन पुलिस को सौंपे आवेदन में कहा कि इन दिनों भारत के प्रयागराज तीर्थस्थल पर महाकुंभ

का वृहद आयोजन चल रहा है और इस अवसर पर न केवल भारत, अपितु विदेशों से भी लगभग 45 करोड़ सनातन धर्मप्रेमी प्रयागराज पहुँचकर माँ गंगा के पवित्र त्रिवेणी संगम स्थल पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने पुराणों और शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया, तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी रसागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। देवताओं के 12 दिन, पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए हर 12 साल में महाकुम्भ का आयोजन किया जाता है। भाजपा प्रदेश महामंत्री वास्तव, जिलाध्यक्ष ठाकुर, प्रदेश मीडिया चिमनानी, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक चंद्रवंशी और सह संयोजक पांडे ने कहा कि भगवान शंकर ने इस मंथन से निकले हलाहल को अपने कंठ में धारण कर अखिल ब्रह्माण्ड की रक्षा की थी। बाद में भागीरथी के आह्वान पर माँ गंगा भू-लोक में अवतरित हुई सनातन संस्कृति का यह अटूट विश्वास है कि माँ गंगा के पवित्र त्रिवेणी संगम में अस्थियों के विसर्जन से मृत लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

छात्राओं ने जाना यातायात के नियम

रायपुर। गुरुकुल महिला महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एंटी रैगिंग कमेटी की संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में यातायात प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ प्रशांत शुक्ला ने महाविद्यालय के छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी और नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही सड़कों को सुरक्षित बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर श्री उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह , यातायात प्रशिक्षक टीके भोई, सहायक प्रशिक्षक सहदेव राम वर्मा एवं सुनीता चंसोरिया, प्राचार्य डॉक्टर संध्या गुप्ता व कार्यक्रम अधिकारी डॉ रात्रि लहरी उपस्थित थे। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक विगत दिवस से चौक- चौराहो मे ट्रैफिक वार्डन की भूमिका मे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे है।

गुरजीत सिंह ने छात्राओं को दो पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट पहनने की सलाह दी और उसकी महत्ता के बारे में बताया और सड़क हादसे में घायल की मदद कर अपनी जिम्मेदारियां को पूरा करने की बात कही, साथ ही यातायात नियमो का प्रचार प्रसार एवं जागरूक करने का संकल्प दिलाया। टी के भोई ने यातायात नियमों के साथ

मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यातायात नियमों और संकेत के बारे के साथ ही पांच प्रकार के चालान के बारे में चर्चा के साथ हेल्पलाइन नंबर 9479191234 की जानकारी दी। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए 10 नियमों का पालन करने को कहा जिससे हम सब दुर्घटनाओं को कम कर सके। प्राचार्य डॉक्टर संध्या गुप्ता ने कहा कि शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रचार अभियानों के माध्यम से लोगों में सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी और जागरूक करना चाहिए। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के एंटी रैगिंग के प्रभारी डॉ. कविता सिलवाल, डॉ राजेश अग्रवाल, डॉ वंदना अग्रवाल डॉ सिमरन आर वर्मा, डॉ देव श्री वर्मा, प्रीति साहू, अंशिका दुबे,डॉ टीनू दुबे, आराधना सिंह, डॉ ज्योति अग्रवाल,तृप्ति द्विवेदी मान्य शर्मा, डॉ अनुराधा गुप्ता समस्त प्राध्यापक एवं छात्राएं उपस्थित रहे।

बृजमोहन ने प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की रेल मंत्री से की मांग

रायपुर। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रद्धालुओं को प्रयागराज महाकुंभ स्नान हेतु विशेष ट्रेन सुविधा प्रदान करने के लिए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और रायपुर मंडल के डीआरएम को पत्र लिखा है।

श्री अग्रवाल के मुताबिक ने उनके लोकसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण महाकुंभ स्नान हेतु प्रयागराज जाना चाहते हैं लेकिन वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनों की संख्या सीमित होने के कारण यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

सांसद श्री अग्रवाल ने मांग की है कि रायपुर अथवा दुर्ग से प्रयागराज तक महाकुंभ अवधि के लिए विशेष ट्रेन आरंभ की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को इस पवित्र स्नान का अवसर सहजता से प्राप्त हो सके। उन्होंने रेल मंत्री और डीआरएम से अनुरोध किया है कि श्रद्धालुओं की इस आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं।

सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा पर्व है, जिसमें देश के कोने-कोने से लोग श्रद्धा और आस्था के साथ शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को इस धार्मिक आयोजन में भाग लेने में कोई बाधा न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भाजपा सरकार अपने वादा पूरे नहीं किए: दीपक बैज

रायपुर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस के मुद्दे और प्रत्याशी दोनों मजबूत है हम स्थानीय चुनाव में जीत का रिकार्ड दोहरायेंगे। कांग्रेस इन स्थानीय निकाय के चुनावों में न सिर्फ अपनी पिछली जीत दोहरायेगी,

अबकी बार और अधिक पंचायत एवं निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत कर आयेंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वातारण है। लोग प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, रोज हो रही हत्याओं, बलात्कार, लूट, चाकूबाजी की घटनाओं के कारण सरकार से निराश है, भाजपा की साय सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में जनता को निराश किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने जनता से जो वादा किया था, एक साल में उसको पूरा नहीं किया है। न 500 रू. सिलेंडर देने का वादा पूरा किया और न ही 18 लाख आवास देने का वादा पूरा किया। भाजपा राज में बिजली के दाम बढ़ गये है। कांग्रेस शासनकाल में 400 यूनिट तक बिजली के दामों में 50 प्रतिशत छूट को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है, जनता भाजपा के खिलाफ निकाय चुनावों में मतदान करेगी।

भाजपा ने किसानों, आवासहीनों दोनों को धोखा दिया है: शुक्ला

रायपुर । उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पत्रकार वार्ता का जबाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब-जब चुनाव आता है भाजपा के नेता झूठ की खेती करना शुरू कर देते है। स्थानीय निकाय चुनाव

के पहले फिर किसानों और आवास हीनों को ठगने का काम शुरू हो गया। भाजपा नेता झूठ बोल रहे है कि साय सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया है। साय सरकार ने एक साल मे एक भी मकान नहीं बनाया है जिन डेढ़ लाख मकानों को बनाने का दावा गृहमंत्री कर रहे है वह तो भूपेश सरकार ने स्वीकृत किया था और उसका पहला किस्त भी कांग्रेस सरकार ने डाला था। भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय सरकार के तथाकथित प्रधानमंत्री आवास केवल विज्ञापनों और होल्डिंग तक ही सीमित रह गया है, हकीकत भाजपा की सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ में एक भी हितग्राही के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। उल्टे पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ आवास न्याय योजना भी अघोषित तौर पर बंद कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से मोर ज़मीन मोर मकान योजना पर भी ग्रहण लग चुका है।

छात्र कौशल विकास कार्यक्रम पर किए हस्ताक्षर

रायपुर। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई और छत्तीसगढ़ सरकार ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र में राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत पूरे राज्य में स्टूडेंट स्किलिंग प्रोग्राम की सुविधा दी जाएगी। मुकेश बंसल,सेक्रेटरी- फाइनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शियल टैक्स (जीएसटी) और सेक्रेटरी- चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ सरकार; और श्रीराम कृष्णन, चीफ बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर, एनएसई, द्वारा आज छत्तीसगढ़ में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से एनएसई, पूरे राज्य में स्टूडेंट स्किलिंग प्रोग्राम की सुविधा प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा) क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना, कौशल और क्षमता का निर्माण करना है। इस प्रोजेक्ट से बीएफएसआई क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कौशल विकास, जो रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट और केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति (2020) के मुख्य पहलुओं में से एक है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार के उद्देश्य के साथ बखूबी मेल खाता है और राज्य के युवाओं को बीएफएसआई क्षेत्र में आवश्यक कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाने के लिए तैयार है।

कांग्रेस में टूट- फूट शुरू, दो पार्षदों ने पार्टी को कहा अलविदा

रायपुर । छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए रायपुर के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची के बाद से ही घमासान मचा हुआ है। दो सीटिंग पार्षदों बंटी होरा, जितेंद्र अग्रवाल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब ये दोनों पार्षद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव पूनम पांडेय ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के कुछ और सीटिंग पार्षद टिकट कटने से नाराज हैं। महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव पूनम पांडेय ने भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के कुछ और सीटिंग पार्षद टिकट कटने से नाराज हैं। पूनम पाण्डेय ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा कि, मैं पूनम पांडे वर्तमान पद महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव के पद से अभी आज से पद मुक्त होते हुए इस्तीफा देती हूं। मैं पत्रकारिता छोड़कर लगातार कांग्रेस पार्टी में कई सालों से महिला कांग्रेस पद में रहते हुए पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी के हित में काम कर रही थी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए लंबे समय के इन्तजार के बाद कांग्रेस ने रायपुर शहर के लिए सूची जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार, इस बार कई सीटिंग पार्षदों की टिकट कटी है तो वहीं नए चेहरों को मौका दिया गया है। एजाज ढेबर को पं. भगवतीचरण शुक्ल वार्ड से टिकट मिला है। कांग्रेस की जारी सूची के अनुसार, श्रीकुमार मेनन को रामकृष्ण परमहंस वार्ड में टिकट मिली है।

86वीं इंटर स्टेट सब जुनियर टेबल टेनिस टीम घोषित

रायपुर। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के तत्वावधान में मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ द्वारा इंदौर (मध्यप्रदेश) में 30 जनवरी से 7 फरवरी 2025 तक 86वीं इंटर स्टेट सब जुनियर एवं कैडेट राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें 30 जनवरी से 2 फरवरी तक होप्स (अंडर-11) बालिका एकल, कैडेट (अंडर-13) बालिका एकल/युगल वर्ग एवं सब जुनियर (अंडर-15) बालिका टीम/एकल/युगल वर्ग तथा दिनांक 04/02/2025 से 07/02/2025 तक होप्स (अंडर-11) बालक एकल, कैडेट (अंडर-13) बालक एकल/युगल वर्ग एवं सब जुनियर (अंडर-15) बालक टीम/एकल/युगल वर्ग की प्रतियोगिता होगी। उक्त प्रतियोगिता हेतु छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष श्री शरद शुक्ला द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के होप्स, कैडेट एवं सब जुनियर (बालक एवं बालिका) टीम की घोषणा की गयी। इस अवसर पर पदाधिकारी श्री विनय बैसवाड़े, श्री प्रदीप जोशी, श्री रजनीश ओबेराय सहित सभी पदाधिकारियो ने टीम को शुभकामनाए दी एवं अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जतायी। प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य कि होप्स, कैडेट एवं सब जुनियर बालिका टीम मंगलवार को रवाना हुयी तथा होप्स, कैडेट एवं सब जुनियर बालक टीम 2 फरवरी को रवाना होगी। टीम के कोच श्री एम. रविराज (दुर्ग) एवं मेनेजर श्रीमती अपर्णा पांडे (रायपुर) है।

आईआईएम रायपुर में पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर पर आयोजन

अहिल्याबाई ने भारतवर्ष को सांस्कृतिक सूत्र में पिरोया : वर्मा

रायपुर। भारतीय प्रबंधन संस्थान ,अटल नगर रायपुर में पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी समारोह के अवसर पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. टोपलाल वर्मा जी एवं संस्थान के कुलसचिव कर्नल हरिन्द्र त्रिपाठी जी ने पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण किए उसके उपरांत शास्त्रीय संगीत से लयबद्ध सरस्वती वंदन एवं मातृभाषा से परिष्कृत मंच संचालन के साथ कार्यक्रम का विधिवत आरंभ हुआ। मुख्य वक्ता डॉ टोपलाल जी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर

जी के जीवन के कुछ प्रमुख बातें भी बतायें -अहिल्याबाई होलकर पूरे 18 विधाओं में निपुण थी। वे 28 वर्षों तक कुशल प्रशासक रही। शिवाजी महाराज का राज्य अष्ट प्रधान होता था, अहिल्याबाई होल्कर जी ने 37 प्रधान बनाए। पूरे मालवा में गुरुकुल की स्थापना की। अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए 19अध्येताओं की नियुक्ति किए। इस युग में केवल एक को ही पुण्य श्लोक की उपाधि। इसके पूर्व राजा नल,युधिष्ठिर को यह उपाधि।कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। पर किसी ने यदि किया तो उसे छोड़ा भी नहीं।पुत्री का विवाह जनजातीय युवक से किया। आतंकियों को मालवा से मुक्त करवाने की शर्त पर।

इतने समय के बाद भी भारत जीवित है तो अपने इन्ही सांस्कृतिक मूल्यों के कारण जीवित है। मुख्य वक्ता डॉ. टोपलाल वर्मा ने लोकमाता के जीवन के कुशल संयोजन, लोक प्रशासन, न्याय, कर्मठता ,दूरदर्शिता, समरसता और पर्यावरण जैसे विविध पहलुओं को लेकर विषय का सुंदर व सुगठित स्वरूप छात्रों के समक्ष रखा। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम अर्थात् केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम,सोमनाथ से लेकर जगन्नाथ पुरी तक माता अहिल्या के द्वारा मंदिरों का जीर्णोद्धार कर समूचे भारतवर्ष को सांस्कृतिक सूत्र में पिरोया। केवल जीर्णोद्धार ही नहीं अपितु मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हुए प्रत्येक स्थान पर धर्मशालाओं एवं भोजनालयो की भी व्यवस्था की। बाल्यकाल से ही कुशल संयोजन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सैन्य कार्यों में निपुणता प्राप्त की। बालिकाओं को शास्त्र और शस्त्र दोनों की समानांतर शिक्षा प्रदान करने को महत्व दिया। पूरे देश में गुरुकुल की स्थापना की। अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए 19 अध्येताओं की नियुक्ति की।अनुशासन और न्याय सर्वोपरि ऐसा मानने वाली अहिल्या माता उनके समक्ष अपने अधिकारी या पुत्र को भी दंड देने से परहेज नहीं करती थी।

एनटीपीसी ने सिम्स में चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु दिये 2.92 करोड़ रूपए

जिला प्रशासन और एनटीपीसी के मध्य हुआ एमओयू*

बिलासपुर। एनटीपीसी सीपत ने सीएसआर मद से सिम्स में चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु दिये 2.92 करोड़ रूपए का सहयोग किया है। जिलाधीश कक्ष में सिम्स हेतु जीवन रक्षक उपकरणों के लिए जिला प्रशासन की ओर डॉ. लखन सिंह, चिकित्सा अधीक्षक सिम्स चिकित्सालय बिलासपुर एवं डा. सामंत सीएमएचओ, एनटीपीसी सीपत के मध्य 2.92 करोड़ रूपये के एम.ओ.यू में हस्ताक्षर किया गया । कलेक्टर अवनीश शरण की मौजूदगी में निष्पादित एमओयू में मुख्य रूप से अमित कुमार, आयुक्त नगर निगम बिलासपुर, डा. रमणेश मूर्ति अधिष्ठाता, डॉ. लखन सिंह सिम्स चिकित्सा अधीक्षक सिम्स चिकित्सालय, सत्यकाम एनटीपीसी सीपत, डा. सामंत सीएमएचओ, एनटीपीसी सीपत, एवं व्ही. के. पाण्डेय, परियोजना प्रमुख, एनटीपीसी सीपत उपस्थित थे।ज्ञात हो कि कलेक्टर बिलासपुर द्वारा

सिम्स चिकित्सालय का विभिन्न अवसरों परनिरीक्षण किया गया था।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को कई विभागों में उपकरणों की कमी की जानकारी दी गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा का विस्तार करने हेतु एनटीपीसी सीपत से सी.एस.आर. मद से 2.92 करोड़ रूपये के उपकरणों की उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये थे। इस राशि से विभिन्न विभागों में आवश्यकतानुसार उपकरणों की खरीदी यथाशीघ्र कर विभागों में प्रदाय किया जायेगा। सिम्स चिकित्सालय में बिलासपुर संभाग के साथ-साथ प्रदेश सहित अन्य समीपवर्ती प्रदेशों से मरीज इलाज हेतु आते हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.